



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15—जनवरी 21, 2011 (पौष 25, 1932)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15—JANUARY 21, 2011 (PAUSA-25, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

सं. राआबैंक एचएफसी.निर्देश.2/सीएमडी/2010--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने देश के लाभार्थ आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कम्पनी (रा. आ. बैंक) निर्देश, 2010 (अबके बाद जिन्हें "प्रमुख निर्देश" संदर्भित किया जाएगा) में, इसके अतिरिक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, यथा :

1. मूल निर्देशों में अनुच्छेद 27 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, यथा :

"27 ए. मूल्य अनुपात हेतु ऋण (एलटीवी)

"कोई भी आवास वित्त कम्पनी (i) 90% से अधिक एलटीवी अनुपात के साथ 20 लाख रुपये से अधिक व्यक्तिगत आवास ऋण प्रदान नहीं करेगी और (ii) अन्य दूसरे 20 लाख रुपये से अधिक के व्यक्तिगत आवास ऋण 80% से अधिक एलटीवी अनुपात के साथ करेगी।"

2. मूल निर्देशों के अनुच्छेद 28 के उप-अनुच्छेद (1) में, धारा (iv) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :

- “iv मानक आस्तियां
- (क) व्यक्तिगत हेतु, आवास ऋणों के अलावा सभी अन्य ऋणों के सापेक्ष मानक आस्तियां (जिसके अंतर्गत भवन निर्माताओं/कम्पनियों/एजेंसियों के लिए आवास ऋण तथा अन्य उद्देश्यों तथा सम्पत्ति के खिलाफ ऋण आदि शामिल होंगे)
- (ख) टीजर/विशेष दरों पर दिये आवास ऋणों के बारे में मानक आस्तियां यथा शुरू में कुछ वर्षों तक तुलनात्मक दृष्टि से कम व्याज दर पर जिसके बाद दरों का पुनः निर्धारण उच्च दरों पर किया जाएगा।
- (ग) व्यक्तिगत आवास ऋणों के मामले में सम्पत्ति/ऋणकर्ता के बीमा के लिये दिये गए ऋणों के बारे में मानक आस्तियां
3. मूल निर्देशों के अनुच्छेद 30 के उप-अनुच्छेद (3)(2) में, धाराएं (बी)(ii) और (बी)(iii) में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा, यथा:
- (बी)(ii) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 30 लाख रु. से अधिक किंतु 75 लाख रु. से कम संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जहां एलटीवी अनुपात है = या < 75% 75%
- (बी)(iii) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 75 लाख रु. तक का संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जहां एलटीवी अनुपात है > 75% 100%
- (बी)(iv) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 75 लाख रु. से अधिक संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है। 125%
- (बी)(v) व्यक्तिगत आवास ऋणों के मामले में सम्पत्ति/ऋणकर्ता के बीमा के लिये दिया गया ऋण संबंधित आवास ऋण के बारे में लागू अनुसार
4. अनुसूची II में, भाग घ में
- III(एफ)(iii) और (iv) में दिये मदों के विवरण, मद कोड और जोखिम भार के लिये, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :
- (iii) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 30 लाख रु. से अधिक किंतु 75 लाख रु. से कम संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जहां एलटीवी अनुपात है = या < 75% 237(iii) 75
- (iv) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 30 लाख रु. से अधिक किंतु 75 लाख रु. तक का संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जहां एलटीवी अनुपात है = या > 75% 237(iv) 100
- (v) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 75 लाख रु. से अधिक संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है। 237(iv) 125

व्यक्तिगत हेतु आवास ऋण के अलावा कुल बकाया ऋणों के सामान्य प्रावधान का 0.4% निम्नानुसार किया जाए:

- (1) 0.2% 31 मार्च, 2011 तक
(2) 0.4% 31 सितम्बर, 2011 तक

ऐसे ऋणों की कुल बकाया राशि पर 2% प्रावधान। एक वर्ष के बाद इन ऋणों के प्रावधान को उच्च दरें पुनः निर्धारित करने की तारीख से, यदि लेखा 'मानक' रहता है, पुनः निर्धारित किया जाएगा।

शून्य

- (vi) व्यक्तिगत आवास ऋणों के मामले में सम्पत्ति/ऋणकर्ता के बीमा के लिये 237(iv) संबंधित आवास ऋण के बारे में लागू अनुसार

आर. वी. वर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वित्त मंत्रालय
(कार्पोरेशन बैंक)

मंगलूर, दिनांक

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, कार्पोरेशन बैंक का निदेशक-मण्डल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (i) ये विनियम कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 कहलाएंगे।
- (ii) संबंधित विनियमों में अन्यथा न सूचित करने पर ये विनियम 2 जून 2005 से लागू होंगे।
2. कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में (यत्पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) विनियम 3 में, :--

- (i) निम्नलिखित खण्ड, खण्ड (छ) का स्थान लेगा, अर्थात् :--

‘(छ) “परिवार” से अधिकारी की पति/पत्नी (जो बैंक का कर्मचारी नहीं है), पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (आश्रित और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित) और सामान्यतः उक्त अधिकारी के साथ रहनेवाले और पूर्णतः आश्रित माता-पिता अभिप्रेत है’;

- (ii) निम्नलिखित खण्ड, खण्ड (ण) का स्थान लेगा अर्थात् :--

‘(ण) “पूर्णतः आश्रित बच्चे या माता-पिता” से रु. 2,250/- प्रति माह से कम आय वाले बच्चे या माता-पिता अभिप्रेत है’।

टिप्पणी : यदि माता-पिता में से किसी एक की आय रु. 2,250/- प्रति माह से अधिक है या माता-पिता दोनों की आय मिलाकर रु. 2,250/- प्रति माह से अधिक है तो माता-पिता दोनों को संबंधित अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा;’

3. उक्त विनियमों में, विनियम 4 में, निम्नलिखित उप-विनियम, उप-विनियम (4) का स्थान लेगा, अर्थात् :--

- (4) नवम्बर 2002 को या उसके बाद से प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे :--

- (क) उच्च कार्यपालक श्रेणी:

$$\text{वेतनमान VII} = \text{रु. } 29,340 - \frac{680}{2} - 30,700 - \frac{900}{1} - 31,600 - \frac{1,000}{1} - 32,600$$

$$\text{वेतनमान VI} = \text{रु. } 26,620 - \frac{680}{4} - 29,340$$

- (ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी:

$$\text{वेतनमान V} = \text{रु. } 24,140 - \frac{620}{4} - 26,620$$

$$\text{वेतनमान IV} = \text{रु. } 20,480 - \frac{560}{1} - 21,040 - \frac{620}{2} - 24,140$$

(ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी:

$$\text{वेतनमान III} = \text{रु. } 18,240 - \frac{560}{5} - 21,040 - \frac{620}{2} - 22,280$$

$$\text{वेतनमान II} = \text{रु. } 13,820 - \frac{500}{1} - 14,320 - \frac{560}{10} - 19,920$$

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी:

$$\text{वेतनमान I} = \text{रु. } 10,000 - \frac{470}{6} - 12,820 - \frac{500}{3} - 14,320 - \frac{560}{7} - 18,240$$

टिप्पणी : दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 को लागू वेतनमान द्वारा शासित प्रत्येक अधिकारी को दिनांक 01 नवम्बर, 2002 को इस विनियम में निर्दिष्ट वेतनमान में नियतन प्रक्रम-वार किया जाएगा, अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुसूची प्रक्रमों के अनुसार किया जाएगा और जहाँ अन्यथा उपबंधित न हो, वेतनवृद्धि हमेशा की भाँति, वर्ष पूरा होने की तारीख को देय होगी;

(4क) उप-विनियम (1), (2), (3) और (4) में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।'

4. उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम, विनियम 5 का स्थान लेगा, अर्थात् :-

वेतनवृद्धि - (1) विनियम 4 के उप-विनियम (4) के प्रावधान के अधीन 01 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद निम्नलिखित शर्तों के अधीन वेतनवृद्धि दी जाएगी, अर्थात् :-

- (क) विनियम 4 में निर्धारित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्याधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी;
 - (ख) वेतनमान I तथा वेतनमान II के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुँचने के बाद एक वर्ष पश्चात् अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि सहित आगे की वेतनवृद्धि केवल नीचे (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर दी जाएंगी बशर्ते कि उन्होंने सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दक्षता रोध को पार किया हो;
 - (ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II या III के अधिकतम तक पहुँचनेवाले अधिकारियों को, यथास्थिति, वेतनमान II या III के अधिकतम प्रक्रम पर पहुँचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि दी जाएगी/जाएंगी, वेतनमान II के अंतिम प्रक्रम पर पहुँच चुके अधिकारियों के मामले में प्रत्येक रु. 560/- की अधिक-से-अधिक दो वेतनवृद्धि दी जाएगी तथा वेतनमान III के अंतिम प्रक्रम में पहुँच चुके अधिकारियों के मामले में रु. 620/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी;
- बशर्ते कि 01 नवम्बर, 1994 को और उसके बाद से सब्सटान्तिव वेतनमान III के अधिकारी अर्थात् जो वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नति किए जाते हैं, वे पहली अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होने के बाद तीन वर्षों के बाद दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे;

बशर्ते यह भी कि अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि/अवरोध वेतनवृद्धि ऐसे अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो पदोन्नति देने पर इसका इनकार करते हैं।

टिप्पणी : अगले उच्चतर वेतनमान में दी गई ऐसी वेतनवृद्धि को पदोन्नति नहीं माना जाएगा। ऐसी वेतनवृद्धि पाने के पश्चात् भी अधिकारियों को, यथास्थिति अपने सब्सटान्तिव वेतनमान I या II के विशेषाधिकार, परिलब्धियाँ, कर्तव्य, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलते रहेंगे।

- (2) भारतीय बैंकर संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट का भाग I/भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्था का जूनियर एसोसिएट और भारतीय बैंकर संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट का भाग II परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक-एक वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण :

- (क) जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले भारतीय बैंकर्स संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट परीक्षा का भाग I या भाग II उत्तीर्ण किया है, उसे नियत तारीख से यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि या वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो।
- (ख) 01 नवम्बर, 1987 को या उसके बाद से वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने वाले अथवा पहुँच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हो, तो उसके अधीन निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार अतिरिक्त वेतनवृद्धि के स्थान पर व्यावसायिक योग्यता भत्ता दिया जा सकता है :--

तालिका

- | | |
|--|--|
| जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है | (i) एक वर्ष पश्चात् रु. 100/- प्रति माह जिसमें रु. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे। |
| जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं | (i) एक वर्ष पश्चात् रु. 100/- प्रति माह जिसमें रु. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।
(ii) दो वर्ष पश्चात् रु. 250/- प्रति माह जिसमें रु. 200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे। |
- (ग) 01 नवम्बर, 1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होते हुए, व्यावसायिक योग्यता भत्ते की पात्रता निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार संशोधित की जाती है :--

तालिका

- | | |
|--|--|
| जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है | (i) एक वर्ष पश्चात् रु. 120/- प्रति माह जिसमें रु. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे। |
| जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं | (i) एक वर्ष पश्चात् रु. 120/- प्रति माह जिसमें रु. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।
(ii) दो वर्ष पश्चात् रु. 300/- प्रति माह जिसमें रु. 200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे। |

बशर्ते कि विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) के अनुसार जो अधिकारी नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं, वे ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के एक या दो वर्ष पश्चात् यथास्थिति भाग I और II हेतु, व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त करेंगे।

- (घ) 01 नवम्बर, 1999 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होते हुए, व्यावसायिक योग्यता भत्ते की पात्रता निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार संशोधित की जाती है :--

तालिका

- | | |
|--|---|
| जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान का जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान सर्टिफाइड एसोसिएट का भाग I उत्तीर्ण किया है : | (i) वेतनमान में अधिकतम पहुँचने के एक वर्ष पश्चात् रु. 150/- प्रति माह। |
| जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान का जूनियर एसोसिएट और भारतीय बैंकर्स संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं : | (i) वेतनमान में अधिकतम पहुँचने के एक वर्ष पश्चात् रु. 150/- प्रति माह।
(ii) वेतनमान में अधिकतम पहुँचने के दो वर्ष पश्चात् रु. 360/- प्रति माह। |

बशर्ते जो अधिकारी वेतनमान I और वेतनमान II में हैं और जिन्हें उप-विनियम (1) के खण्ड में विनिर्दिष्टानुसार अगले उच्चतर वेतनमान में आगे की वेतनवृद्धि प्रदान की गई है, वे ऐसे उच्चतर वेतनमानों में अधिकतम तक पहुँचने के यथास्थिति, एक या दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त करेंगे।

- (ड) 01 नवम्बर, 2002 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होते हुए, व्यावसायिक योग्यता भत्ते की पात्रता निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार संशोधित की जाती है :--

तालिका

जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान का जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट का भाग I उत्तीर्ण किया है

- (i) वेतनामन में अधिकतम पहुँचने के एक वर्ष पश्चात् रु. 300 प्रति माह।

जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं

- (i) वेतनामन में अधिकतम पहुँचने के एक वर्ष पश्चात् रु. 300 प्रति माह।

- (ii) वेतनामन में अधिकतम पहुँचने के दो वर्ष पश्चात् रु. 750 प्रति माह।

बशर्ते जो अधिकारी वेतनमान I और वेतनमान II में हैं और जिन्हें उप-विनियम (1) के खण्ड में विनिर्दिष्टानुसार अगले उच्चतर वेतनमान में आगे की वेतनवृद्धि प्रदान की गई है, वे ऐसे उच्चतर वेतनमानों में अधिकतम तक पहुँचने के यथास्थिति, एक या दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त करेंगे।

टिप्पणी :

- (i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक योग्यता वेतन मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे उक्त वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धि की सीमा तक भारतीय बैंकर्स संस्थान का जूनियर एसोसिएट/भारतीय बैंकर्स संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट उत्तीर्ण करने हेतु अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी और यदि उक्त वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी वेतनवृद्धि के एवज में व्यावसायिक योग्यता भत्ता पाने हेतु पात्र होगा।
- (ii) 01 नवम्बर, 1994 को और इस तारीख से यथास्थिति, व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन, महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अधिवर्षिता लाभ के लिए गिना जाएगा।
- (iii) यदि कोई अधिकारी पदोन्नति देने पर इसका इनकार करता है तो वह उपर्युक्तानुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन के लिए पात्र नहीं होगा।
- (iv) यदि कोई अधिकारी वेतनमान में अधिकतम पहुँचने के बाद भारतीय बैंकर्स संस्थान का जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर संस्थान का सर्टिफाइड एसोसिएट (कोई एक या दोनों भाग) अर्जित करता है, तो उसे ऐसी योग्यता अर्जित करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की परवर्ती किस्त को जारी किया जाना व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त जारी करने की तारीख के आधार पर होगा।
- (v) यदि 02 जून, 2005 को कोई अधिकारी ने खण्ड (iv) में उल्लिखित कोई योग्यता अर्जित कर चुका है और उसने उक्त योग्यता अर्जित करने के कारण कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक योग्यता वेतन नहीं प्राप्त किया है तो उसे 01 नवम्बर, 2002 से ऐसी योग्यता/एं प्राप्त करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, उपर्युक्तानुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी किया जाएगा।

- 3.(क) सभी अधिकारी जो 01 नवम्बर, 1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं, उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त होगी। 01 नवम्बर, 1993 को जो अधिकारी परिवीक्षाधीन हैं, उन्हें स्थायीकरण के एक वर्ष बाद अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।

टिप्पणी : अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि के दिनांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

- (ख) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर हैं या जिन्हें 01 नवम्बर, 1993 को अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त है, वे 01 नवम्बर, 1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता आहरित करेंगे जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि राशि और 01 नवम्बर, 1993 को उस पर देय महंगाई भत्ता राशि और विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते के समतुल्य राशि होगी तथा निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार नियत वैयक्तिक भत्ता और मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, इसके अंतर्गत दिए गए मकान किराया भत्ते सहित नियत वैयक्तिक भत्ता, यदि कुछ हो, आगे संशोधित होने तक वैध रहेगा :--

तालिका		
वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर 01.11.1993 को महंगाई भत्ता	जहाँ बैंक का आवास दिया जाता है, वहाँ देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क) रु.	(ख) रु.	(ग) रु.
230/-	5.79/-	236/-
250/-	6.30/-	257/-
300/-	7.56/-	308/-
400/-	10.09/-	411/-

- (ग) 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद से, अन्य बातें समान होते हुए नियत वैयक्तिक वेतन, मकान किराया भत्ते के साथ, यदि कुछ हो तो, निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार होगा :--

तालिका		
वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर 1.11.1997 को महंगाई भत्ता	जहाँ बैंक का आवास दिया जाता है, वहाँ देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क) रु.	(ख) रु.	(ग) रु.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

- (घ) 1 नवंबर, 2004 को या उसके बाद से, अन्य बातें समान होते हुए नियत वैयक्तिक वेतन, मकान किराया भत्ते के साथ, यदि कुछ हो तो, निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर होगा :--

तालिका

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर 1.11.2002 को महँगाई भत्ता	जहाँ बैंक का आवास दिया जाता है, वहाँ देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क) रु.	(ख) रु.	(ग) रु.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

टिप्पणी : (i) विनियम 5 के खण्ड (ख), (ग) और (घ) में दी गई तालिकाओं के स्तंभ (ग) के अधीन सूचितानुसार नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को दिया जाएगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया जाता है।

(ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन (क) + (ख) + विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख), (ग) और

(घ) में उल्लिखितानुसार संबंधित अधिकारी द्वारा तब आहरित मकान किराया भत्ता होगा जब विनियम 4 के उप-विनियम (2) और (3) में निर्दिष्टानुसार संबंधित वेतनमान का वेतनवृद्धि घटक अर्जित करता है।

(iii) 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद से नियत वैयक्तिक वेतन जारी करने की वजह से उप-विनियम (2) के अधीन स्पष्टीकरण (ग) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता भत्ता जारी करने की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा :

बशर्ते कि जहाँ व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त जो पूर्व प्रावधानों की वजह से एक वर्ष के लिए आगे बढ़ायी गयी है और 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी करने के लिए नियत की गई है, वह अधिकारी को उस तिथि को और उस तिथि से जारी की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कुछ हो तो, 1 नवंबर 2000 को जारी की जाएगी।

(iv) नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभ के लिए गिना जाएगा।

(ड.) जिस अधिकारी ने उपर्युक्त (क) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि अर्जित की है, वे वेतनमान में अधिकतम पहुँचने के एक वर्ष के बाद ऊपर (ख) या (ग) में बताए गए अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन की मात्रा आहरित करेगा।

5. उक्त विनियम में, विनियम 21 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

(4) 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद, महँगाई भत्ता योजना निम्नवत् होगी :

(क) महँगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960 = 100 की तिमाही औसत में 2288 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से देय होगा।

(ख) 1 नवंबर, 2002 से 31 जनवरी, 2005 तक की अवधि के दौरान महँगाई भत्ता निम्न दरों पर देय होगा :--

(i) रु 9650 तक 'वेतन' का 0.18% और;

(ii) रु. 9,650 से अधिक रु. 15,350 तक 'वेतन' का 0.15% और;

(iii) रु. 15,350 से अधिक रु. 16,350 तक 'वेतन' का 0.09% और;

(iv) रु. 16,350 से अधिक 'वेतन' का 0.04%

(ग) 1 फरवरी, 2005 से महँगाई भत्ता वेतन के 0.18% पर देय होगा।

टिप्पणी : (क) महँगाई भत्ते के लिए “वेतन” का अर्थ होगा अवरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन।

(ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग), (घ), और (ड.) में विनिर्दिष्टानुसार महँगाई भत्ते के लिए व्यावसायिक योग्यता भत्ता/व्यावसायिक योग्यता वेतन गिना जाएगा।

6. उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम, विनियम 22 का स्थान लेगा, अर्थात् :--

‘22. मकान किराया भत्ता - (1) (क) 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गई है, वहाँ उससे उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के मूल वेतन के 2.5% के समतुल्य राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल की जाएगी।

जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय मकान नहीं दिया गया है, वह 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात् :--

तालिका

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख “क” श्रेणी के शहर तथा समूह “क” में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 9% प्रति माह
(ii) क्षेत्र 1 में स्थित स्थल तथा समूह “ख” में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8% प्रति माह
(iii) क्षेत्र ii में स्थित स्थल अर्थात् उपर्युक्त (i) और (ii) में न आनेवाले सभी स्थल	वेतन का 7% प्रति माह

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है, उसके प्रथम प्रक्रम के 2.5% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 1.50%, जो भी कम हो, होगा।

(2) (क) 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गई है, वहाँ उससे उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के मूल वेतन के 1.75% के समतुल्य राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो वसूल की जाएगी।

जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय मकान नहीं दिया गया है, वह 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात्:--

तालिका

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख “क” श्रेणी के शहर तथा समूह “क” में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5% प्रति माह
(ii) क्षेत्र 1 में स्थित स्थल तथा समूह “ख” में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5% प्रति माह
(iii) अन्य स्थल	वेतन का 6.5% प्रति माह

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है, उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, जो भी कम हो, होगा।

(3) यदि कोई अधिकारी अपने ही मकान में रहता है, तो उसे उप-विनियम 1 के खण्ड (ख) और उप-विनियम (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित परंतुक के ही आधार पर इस प्रकार मकान किराया भत्ता मिलेगा मानो वह नीचे (अ) अथवा (आ) में से उच्चतर के बारहवें भाग के बराबर मासिक किराया दे रहा है :--

निम्नलिखित का योग:--

- (i) निवास स्थान के लिए देय नगर पालिका कर; और
- (ii) भूमि की लागत सहित निवास स्थान की पूँजीगत लागत का 12% और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो उतने भाग की भूमि के आनुपातिक हिस्से की पूँजीगत लागत, किन्तु इसके अंतर्गत वातानुकूलक जैसे विशेष जुड़नार शामिल नहीं होंगे, अथवा

(आ)

निवास स्थान के लिए नगर पालिका कर निर्धारण हेतु आंका गया वार्षिक किराया मूल्य।

स्पष्टीकरण :

(1) इस विनियम के प्रयोजन हेतु “मानक किराया” से अभिप्रेत है :--

- (क) बैंक के स्वामित्व वाले निवास स्थानों के मामले में, सरकार की ऐसे निवास स्थानों के संबंध में प्रचलित पद्धति के अनुसार आंका गया मानक किराया;
- (ख) जहाँ निवास स्थान बैंक द्वारा किराये पर लिया गया है, वहाँ बैंक द्वारा देय संविदागत किराया उपर्युक्त (अ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार परिकलित किराया, जो भी कम हो।

(2) मकान किराया भत्ते के प्रयोजनार्थ “वेतन” का अर्थ होगा अवरोध वेतन सहित मूल वेतन।

(3) 1 नवंबर, 1994 से मकान किराया भत्ते के लिए यथास्थिति व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन गिना जाएगा।

(4) विनियम के उप-विनियम (2) तथा विनियम 23 के प्रयोजनार्थ क्षेत्र I तथा क्षेत्र II का अभिप्राय निम्नलिखित होगा :

- क्षेत्र I - 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान
क्षेत्र II - क्षेत्र I में सम्मिलित न किए गए सभी स्थान।

7. उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम, विनियम 23 का स्थान लेगा, अर्थात् :--

23. अन्य भत्ते :

- (1) 1 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, कोई अधिकारी निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार नगर प्रतिकर भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात्:--

तालिका	
स्थान	दर
(1)	(2)
(क) क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	अधिकतम रु. 540 प्रति माह के अधीन मूल वेतन का 4%
(ख) 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियाँ तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर जो उपर्युक्त (क) में नहीं आते	अधिकतम रु. 375 प्रति माह के अधीन मूल वेतन का 3%
(ग) अन्य स्थान	कुछ नहीं

- (2) 1 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से विशेष क्षेत्र भत्ता इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्टानुसार होगा।
- (3) 1 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से यदि कोई अधिकारी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जिस समूह क या समूह ख के अंतर्गत आनेवाले परियोजना क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तो समूह क या समूह ख के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार वह रु. 210 प्रति माह या रु. 185 प्रति माह की दर पर परियोजना क्षेत्र प्रतिकर भत्ते के लिए पात्र होगा।
- (4) 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को किसी शैक्षिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया जाता है, और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान में स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह परवर्ती स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से संबंधित शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक, पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों के लिए रु. 500 प्रति माह की दर पर मध्य-शैक्षिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा :
 बशर्ते कि यदि सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर पढ़ाई करना बंद करते हैं तो ऐसा भत्ता मिलना बंद हो जाएगा।
- (5) 1 जून, 2005 को या उसके बाद यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्त के पद पर देय परिलब्धियाँ प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त अधिकतम रु. 1500 प्रति माह के अधीन वेतन के 7.75% की दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य सभी भत्ते आहरित कर सकता है जो कि उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में उसे मिलते :
 बशर्ते कि यदि उसे किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो कि उसी स्थान पर स्थित है जहाँ वह अपनी प्रतिनियुक्ति तत्काल पहले तैनात थे, तो वह अधिकतम रु. 750 प्रति माह के अधीन अपने वेतन के 4% के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करेगा।
 बशर्ते यह भी कि यदि किसी अधिकारी को संकाय सदस्य के रूप में बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह अधिकतम रु. 750 प्रति माह के अधीन अपने वेतन के 4% का प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करेगा।
- (6) यदि किसी अधिकारी से किसी समय लगातार सात दिन के लिए या किसी कैलेण्डर महीने के दौरान कुल सात दिन के लिए किसी उच्चतर श्रेणी के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य लिया जाता है, तो उसे स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर अपने वेतन का 6% का स्थानापन्न भत्ता मिलेगा और स्थानापन्न भत्ते को केवल भविष्य निधि या पेंशन के प्रयोजनार्थ वेतन में गिना जाएगा :
 बशर्ते कि जहाँ कोई अधिकारी विनियम 6 के अंतर्गत पदों के प्रवर्गीकरण की समीक्षा के कारण मात्र से उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप में कार्य करता है, तो वह प्रवर्गीकरण की समीक्षा प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।
- (7) यदि किसी अधिकारी को ऐसी शाखा में तैनात किया जाता है जहाँ 1 अप्रैल या 30 सितंबर को लेखा बंदी होती है, तो उसे हरेक लेखा बंदी के लिए रु. 250 का लेखा-बंदी भत्ता दिया जाएगा।
- (8) 1 नवंबर, 2002 को और उसके बाद यदि किसी दिन के दौरान कार्य-समय कम-से-कम दो घंटों के अंतराल के साथ विभाजित किया जाता है, तो वह रु. 125 प्रति माह की दर पर विभाजित ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।
- (9) यदि किसी अधिकारी से छुट्टी के दिन सुरक्षित जमा कक्ष या लॉकर के अभिरक्षक के रूप में कार्य लिया जाता है, तो वह पात्र दरानुसार दैनिक भत्ते के लिए पात्र होगा।
- (10) 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद से, कोई अधिकारी निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार पर्वत एवं ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात्:--

तालिका

स्थान	दर
(i) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊँचाई वाले स्थान	अधिकतम रु. 1150 प्रति माह के अधीन वेतन का 5%
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परन्तु 3000 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान	अधिकतम रु. 500 प्रति माह के अधीन वेतन का 2 1/2%
(iii) 1000 मीटर और उससे अधिक परन्तु 1500 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान और मडिकेरी नगर	अधिकतम रु. 400 प्रति माह के अधीन वेतन का 2%

टिप्पणी : (क) कम-से-कम 750 की ऊँचाई पर स्थित स्थान, जो उससे अधिक ऊँचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हों और जहाँ तक पहुँचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई पार करनी पड़ती हो, पर तैनात अधिकारियों को 1000 मीटर और उससे अधिक ऊँचाई वाले केन्द्रों के लिए देय दर पर पर्वत और ईंधन भत्ता दिया जाएगा।

उपर्युक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आनेवाले किसी भी केन्द्र में फिलहाल दिए जानेवाले पर्वत एवं ईंधन भत्ते को समाप्त किया जाएगा :

बशर्ते कि ऐसे किसी अधिकारी के संबंध में जो ऐसे केन्द्र में 1 मई, 1989 से पूर्व तैनात हो और उसे तारीख के बाद भी उस केन्द्र में तैनात रहा हो, 30 अप्रैल, 1989 को जितना भत्ता वह लेता रहा हो, उसे सुरक्षित रखा जाएगा और तब तक हर माह उसे दिया जाएगा जब तक वह उसी वेतनमान में उस केन्द्र में तैनात रहेगा।

8. उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम, विनियम 24 का स्थान लेगा, अर्थात्:--

24. चिकित्सा सहायता:--

(1) कोई अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात्:--

(क) चिकित्सा व्यय:--1 फरवरी, 2004 को और उस तारीख से, कोई अधिकारी अपने और परिवार के चिकित्सा व्ययों के संबंध में निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार दावा की गई राशियों हेतु लेखा विवरण सहित ऐसा व्यय करने के संबंध में उक्त अधिकारी द्वारा स्वयं अपना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात्:--

तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन श्रेणी	रु. 3,750 या खर्च की गई राशि जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	रु. 5,000 या खर्च की गई राशि जो भी कम हो

टिप्पणी-- (i) किसी अधिकारी को उपयोग न की गई चिकित्सा सहायता राशि को संचित करने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु संचित राशि किसी भी समय ऊपर उल्लिखित अधिकतम राशि से तीन गुना से अधिक नहीं होगी।

(ii) वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति ग्यारह महीनों अर्थात् फरवरी 2004 से दिसम्बर 2004 तक आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

स्पष्टीकरण:--इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी के "परिवार" का अर्थ होगा विनियम 3 के खण्ड (छ) में परिभाषितानुसार परिवार।

- (ख) (i) ऐसे सभी मामलों में जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो, अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक अस्पताल भर्ती संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (ii) 1 मई, 2005 को और उसके बाद इस विनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी को अस्पताल भर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार सीमाओं के अधीन कामगार कर्मचारियों हेतु द्विपक्षीय समझौता दिनांक 2 जून, 2005 के अधीन निर्धारित अस्पताल भर्ती योजना की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी, अर्थात्:--

तालिका

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतन मान I और मध्यम	(i)	बिस्तर प्रभार
प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II व III		स्वयं:--रु. 600 प्रति दिन
		परिवार:--रु. 450 प्रति दिन
	(ii)	अन्य प्रभार--
		कामगार कर्मचारियों को लागू अस्पताल-भर्ती योजना के अंतर्गत
		निर्धारित सीमाओं के 125% की दर पर
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV व V और उच्च	(i)	बिस्तर प्रभार
कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI व VII		स्वयं:--रु. 800 प्रति दिन
		परिवार:--रु. 600 प्रति दिन
	(ii)	अन्य प्रभार--
		कामगार कर्मचारियों को लागू अस्पताल-भर्ती योजना के
		अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 150% की दर पर

- (2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के होते हुए भी और उसे पूर्णतः प्रतिस्थापित करके निदेशक मण्डल, नियत तारीख को बैंक में जो चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) उपलब्ध है, उसमें कोई परिवर्तन किए बिना उन्हें बनाए रखने का निर्णय ले सकता है और यदि निदेशक मण्डल ऐसा निर्णय लेता है तो सभी अधिकारी चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के लिए नियत, तारीख को बैंक में लागू शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार ही चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे।

- (3) निलंबनाधीन अधिकारियों को भी चिकित्सा सहायता और अस्पताल भर्ती सुविधाएं दी जाएंगी।

9. उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम, विनियम 25 का स्थान लेगा, अर्थात्:--

'25. आवास व्यवस्था--(1) कोई अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा।

(2) तथापि यदि बैंक चाहे तो किसी अधिकारी को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है जिसके लिए उक्त अधिकारी 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के मूल वेतन के 1.75% के बराबर की राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान करेगा:

बशर्ते कि ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है तो उसके लिए उससे अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के मूल वेतन के 0.4% के बराबर की राशि वसूल की जाएगी:

बशर्ते यह भी कि जहाँ बैंक द्वारा ऐसा आवास उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ बिजली, पानी, गैस और संरक्षण प्रभार उक्त अधिकारी को देना होगा।

10. उक्त विनियमों में, विनियम 41 में, निम्नलिखित उप-विनियम, उप-विनियम (1) का स्थान लेगा, अर्थात्:-

(1) 2 जून, 2005 को और उसके बाद से, ड्यूटी पर यात्रा करते समय कोई अधिकारी निम्नलिखित के लिए पात्र होगा, अर्थात्:-

- (i) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित 2-टायर शयनयान द्वारा यात्रा करने हेतु पात्र होगा। तथापि, कारोबार की आवश्यकताओं या जनहित को ध्यान में रखते हुए वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से हवाई जहाज (इकॉनमी श्रेणी) द्वारा यात्रा कर सकता है।
- (ii) मध्यम प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित 2-टायर शयनयान द्वारा या यदि यात्रा की दूरी 1000 कि. मी. से अधिक है तो हवाई जहाज (इकॉनमी श्रेणी) द्वारा यात्रा करने हेतु पात्र होगा। तथापि, कारोबार की आवश्यकताओं या जनहित को ध्यान में रखते हुए वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से इससे छोटी दूरी हवाई जहाज (इकॉनमी श्रेणी) द्वारा यात्रा कर सकता है।
- (iii) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या हवाई जहाज (इकॉनमी श्रेणी) द्वारा यात्रा करने हेतु पात्र होगा।
- (iv) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी, ऐसे स्थानों के बीच, जो विमान सेवा या रेल सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं, कार द्वारा यात्रा कर सकता है बशर्ते कि यात्रा की यह दूरी 500 कि. मी. से अधिक न हो। परन्तु यदि उक्त दोनों स्थानों के बीच अधिकांश दूरी विमान या रेल यात्रा द्वारा तय की जा सकती हो तो सामान्यतः केवल शेष दूरी कार द्वारा तय की जानी चाहिए।
- (v) किसी अन्य अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारोबार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं अपने वाहन द्वारा या टैक्सी द्वारा या बैंक के वाहन द्वारा यात्रा करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

(ख) उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित खण्ड, खण्ड (क) स्थान लेगा, अर्थात्:-

(क) विराम भत्ता-1 जून, 2005 को और उसके बाद कोई अधिकारी निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार प्रति दिन विराम भत्ते हेतु पात्र होगा, अर्थात्:-

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	प्रमुख 'क' वर्ग के नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
वेतनमान IV और ऊपर के अधिकारी	रु. 600	रु. 550	रु. 500
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	रु. 550	रु. 500	रु. 400

बशर्ते कि वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों, अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में बाहरी केन्द्र में कार्य हेतु प्रति दिन देय विराम भत्ता रु. 700/- होगा;

बशर्ते यह भी कि जहाँ अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे के कम परन्तु 4 घंटों से अधिक है तो विराम भत्ता उपर्युक्त दरों से आधी दरों पर देय होगा।

स्पष्टीकरण: विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन हेतु “प्रति दिन” का अर्थ होगा चौबीस घंटों की प्रत्येक अवधि या उसका परवर्ती भाग, जिसकी गणना वायुयान द्वारा यात्रा की दशा में प्रस्थान के लिए रिपोर्ट करने के समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहाँ अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटों से कम है, वहाँ “प्रति दिन” का अर्थ होगा कम-से-कम आठ घंटों की अवधि।

(ख) उक्त विनियम में, निम्नलिखित उप-विनियम, उप-विनियम (3) का स्थान लेगा, अर्थात्:-

(4) 1 अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से स्थानांतरित अधिकारी सामान की पैकिंग, स्थानीय परिवहन, उसका बीमा आदि के लिए निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार एकमुश्त राशि पाने का पात्र होगा, अर्थात्,

तालिका

श्रेणी	एकमुश्त राशि
उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ कार्यपालक	रु. 5,000
मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 4,000

बशर्ते कि 1 मई, 2005 को और उसके बाद से इस उप-विनियम के प्रावधान ऐसे प्रभावी होंगे मानो “रु. 5,000” और “रु. 4,000” के अंकों और शब्दों के लिए क्रमशः “रु. 8,750” और “रु. 7,000” शब्दों और अंकों में प्रतिस्थापित किया हो।

11. उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम, विनियम 44 का स्थान लेगा, अर्थात्:-

44 छुट्टी यात्रा रियायत:

- (1) चार वर्षों के प्रत्येक खण्ड के दौरान, कोई अधिकारी दो वर्षों के प्रत्येक खण्ड में एक बार अपने गृह नगर की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत हेतु पात्र होगा या विकल्प के तौर पर वह दो वर्षों के एक खण्ड में अपने गृह नगर और दो वर्षों के दूसरे खण्ड में सबसे छोटे रास्ते से भारत में किसी भी स्थान में यात्रा कर सकता है।
- (2) यथास्थिति, चार वर्षों या दो वर्षों के खण्ड के दौरान किसी भी समय विकल्प का उपयोग करते हुए छुट्टी यात्रा रियायत (गृह नगर की यात्रा के अलावा) का अभ्यर्पण करके नकदीकृत कर सकता है और ऐसा करने पर कप्रश्रे वेतनमान I तथा मप्रश्रे वेतनमान II व III के अधिकारियों के मामले में 4500 किमी (एक तरफा) तथा वप्रश्रे वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में 5500 किमी (एक तरफा) की दूरी तक उसकी पात्रता के अनुसार ट्रेन की यात्रा श्रेणी हेतु लागू किराए के 75% के समतुल्य राशि प्राप्त कर सकता है और अपनी छुट्टी यात्रा रियायत को नकदीकृत करने का विकल्प चुनते समय ऐसे खण्ड या अवधि के दौरान केवल एक बार स्वयं अपने हेतु और अपने परिवार सदस्यों के लिए ऐसा नकदीकरण प्राप्त कर सकता है और छुट्टी यात्रा रियायत के नकदीकरण की सुविधा प्राप्त करते समय छुट्टी यात्रा रियायत के समय ली जानेवाली साधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
- (3) छुट्टी यात्रा रियायत के लिए अधिकारी उसी साधन और श्रेणी का उपयोग कर सकता है जिससे कि वह स्थानांतरण पर यात्रा करते हेतु पात्र है और अधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत के उपयोग की अन्य शर्तें एवं निबंधन निदेशक-मण्डल द्वारा समय-समय पर निश्चित शर्तें एवं निबंधन होंगे।
- (4) चार वर्षों में जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करता है, तब उसे अधिकतम तीस दिनों की साधिकार छुट्टी को अभ्यर्पण कर नकदीकृत करने की अनुमति दी जा सकती है या जब वह दो वर्षों के एक खण्ड में अपने गृह नगर की और दूसरे खण्ड में भारत में किसी भी स्थान में यात्रा करता है, तब उसे प्रत्येक खण्ड में अधिकतम 15 दिन या एक खण्ड में 30 दिन की साधिकार छुट्टी नकदीकृत करने की अनुमति दी जाएगी और छुट्टी नकदीकरण के प्रयोजन हेतु, जिस महीने के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त की जाती है, उस महीने के लिए देय सभी परिलब्धियाँ गिनी जाएंगी:

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी चाहे तो वह एक दिन की अतिरिक्त साधिकार छुट्टी के नकदीकरण की राशि प्रधान मंत्री राहत कोष के लिए दान दे सकता है जिसके लिए उसको बैंक को इस आशय का पत्र देते हुए राशि उक्त कोष में जमा करने का प्राधिकार देना होगा।'

कापॉरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 की अनुसूची

[देखें, विनियम 23 में उप विनियम (2)]

1 नवंबर 2002, से प्रभावी रूप में, इससे पूर्णतः या अंशतः वापस लिए जाते, संशोधित करने तक अधिकारी निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट अनुसार विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए हकदार होंगे, यथा :--

तालिका

क्र. सं. स्थान, जहाँ भत्ता देय हो	देय भत्ते की दर	
	रु. 10,000/- से 14,000/- तक देय	रु. 14,001/- एवं उससे अधिक के लिए देय
1. मिजोरम		
(क) मिजोरम का चिंपतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलेई जिला के लुंगलेई शहर से 25 कि. मी. से अधिक दूरस्थ क्षेत्र	1,000/-	1,300/-
(ख) मिजोरम के लुंगलेई शहर से 25 कि. मी. से अधिक दूरस्थ क्षेत्रों को छोड़कर पूरा लुंगलेई जिला।	800/-	1,050/-
(ग) मिजोरम का पूरा आइजोल जिला।	600/-	750/-
2. नागालैंड	800/-	1,050/-
3. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह		
(क) उत्तर अण्डमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	800/-	1,050/-
(ख) दक्षिण और मध्य अण्डमान, लिटील अण्डमान, निकोबार और नार्कोडम द्वीप समूह	1,000/-	1,300/-
4. सिक्किम	1,000/-	1,300/-
5. लक्षद्वीप समूह	1,000/-	1,300/-
6. असम	160/-	200/-
7. मेघालय	160/-	200/-
8. त्रिपुरा		
(क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	800/-	1,050/-
(ख) दुर्गम क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरा त्रिपुरा	600/-	750/-

क्र. सं. स्थान, जहाँ भत्ता देय हो	देय भत्ते की दर	
	रु. 10,000/- से 14,000/- तक देय	रु. 14,001/- एवं उससे अधिक के लिए देय
9. मणिपुर	600/-	750/-
10. अरुणाचल प्रदेश		
(क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	1,000/-	1,300/-
(ख) दुर्गम क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरा अरुणाचल प्रदेश	800/-	1,050/-
11. जम्मू कश्मीर		
(1) काथुआ जिला	1,000/-	1,300/-
(क) नियाबत बानी		
(ख) लोनी		
(ग) मल्हार		
(घ) मछोड़		
(2) (क) उद्यमपुर जिला	1,000/-	1,300/-
(i) डुडू बसंतगढ़		
(ii) लांदर भमाग इलाका		
(iii) ताकलकोट		
(iv) नागोट		
(ख) मोहरे तहसील के 2(ग) में शामिल न हुए सभी क्षेत्र	1,000/-	1,300/-
(ग) मोहरे तहसील में कम्बन क्षेत्र से गोयल तक और कैसी से अरनास तक के क्षेत्र	800/-	1,050/-
(3) डोडा जिला	1,000/-	1,300/-
किस्तवार जिले के पादर और नियाबत इलाके		
(4) लेह जिला	1,000/-	1,300/-
जिले के सभी स्थानों में		
(5) बारामुला जिला		
(क) गुरेझ-निरबात उप खण्ड व केरन इलाके के सभी स्थान	1,000/-	1,300/-
(ख) माछिल	800/-	1,050/-

क्र. सं. स्थान, जहाँ भत्ता देय हो	देय भत्ते की दर	
	रु. 10,000/- से 14,000/- तक देय	रु. 14,001/- एवं उससे अधिक के लिए देय
(6) पुँछ और रजौरी जिले पुँछ और रजौरी शहरों व दोनों जिलों में स्थित सुन्दरबनी व अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पुँछ और रजौरी जिले के सभी क्षेत्र	600/-	750/-
(7) उपरोक्त (1) से (6) में न आने वाले क्षेत्र, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि. मी. की दूरी के भीतर हो या राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर सीमा भत्ते के लिए योग्य घोषित किया जाता हो।	600/-	750/-
12. हिमाचल प्रदेश		
(1) चंबा जिला		
1. (क) पंगी तहसील	1,000/-	1,300/-
(ख) भरमौर तहसील के निम्नलिखित पंचायत और गाँव (i) पंचायत : बडगाँव, बजोल दियोल कुगती, नयगम और तुण्डा। (ii) गाँव : जगत ग्राम पंचायत का घाटू चौहता ग्राम पंचायत का कनारसी	800/-	1,050/-
2. भरमौर तहसील के उपरोक्त भाग 1ख में शामिल पंचायत और गाँव को छोड़कर।	600/-	750/-
3. झन्डु भाटीयाट तहसील के जनधारू पंचायत, चौरा तहसील, डलहौजी शहर (बनिकेट सहित)		
2. किनौर जिला :		
(क) असरंग, चितकूल और हंगकुनु कगोकूना/चरांग पंचायत, छोटा खंबा ग्राम पंचायत में समाविष्ट 15/20 क्षेत्र, नाथपा और रूपी, पूह उप मंडल, उपरोक्त विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्र को छोड़कर।	1,000/-	1,300/-
(ख) उपरोक्त (क) में निहित से अन्य संपूर्ण जिला	600/-	750/-

क्र. सं. स्थान, जहाँ भत्ता देय हो	देय भत्ते की दर	
	रु. 10,000/- से 14,000/- तक देय	रु. 14,001/- एवं उससे अधिक के लिए देय
(3) कुल्लू जिला :		
3(क) निरमन्द तहसील के 15/20 क्षेत्र, खारगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायत।	1,000/-	1,300/-
(ख) बाहरी-सिराज (जक्ट-खामा के गाँवों और निरमन्द तहसील के बूरो को छोड़कर) और संपूर्ण जिला (सिराज के बाहरी क्षेत्र और पन्द्राबिस परगना को छोड़कर लेकिन निरमाड तहसील के जगतखाना और बुरो क्षेत्र शामिल)	600/-	750/-
(4) लाहूल और स्पीति जिला :		
लाहूल और स्पीति के संपूर्ण क्षेत्र	1,000/-	1,300/-
(5) शिमला जिला :		
(क) कूट, लबाना-सडाना, सारपार और छडी - बरान्दा पंचायत में शामिल रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र।	1,000/-	1,300/-
(ख) डोडरा - कवार तहसील, रामपुर के डरकाली ग्राम पंचायत, कसापथ तहसील और मुनीश, परगना सरहान के गोरी छबीस।	800/-	1,050/-
(ग) चोपाल तहसील और परगना सराहन के गोरीस, पंजगांव, पटसनु, नोबीस और तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र के देवथी ग्राम पंचायत, बाराबीस परगना, रामपुर तहसील के रामपुर परगना के कस्बा रामपुर और गौरी नौ, शिमला शहर और इसके उप नगर धली, जतोग, केसुंप्ती मशोबरा, तारादेवी और तुतु।	600/-	750/-
(6) कांगड़ा जिला :		
(क) बडा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र	800/-	1,050/-
(ख) कांगड़ा जिला के धर्मशाला शहर और नगर सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, लेकिन धर्मशाला शहर में शामिल - वूमन आईटीआई, दरी मैकेनिकल वर्कशॉप, शामनगर, बाल	600/-	750/-

क्र. सं. स्थान, जहाँ भत्ता देय हो	देय भत्ते की दर	
	रु. 10,000/- से 14,000/- तक देय	रु. 14,001/- एवं उससे अधिक के लिए देय

कल्याण और शहर और देश आयोजना
कार्यालय, सकोह, लोवर सकोह के
कांगड़ा सीआरएसएफ कार्यालय,
कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, दुगियार
एचआरटीसी वर्कशॉप, सुधेर,
आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दरी
वन निगम कार्यालय, शामनगर,
चाय कारखाना, दरी, आईपीएच
उप मंडल दान, सैटिलमेन्ट कार्यालय,
शामनगर, बिनवा परियोजना, शामनगर
कार्यालय/जर्सी फार्म, बन्नूरी, सेरिकल्चर
कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल,
बुन्दला, विद्युत उप मंडल, लोहना, डीपीओ
निगम, बुन्दला इलैक्ट्रिकल एचपीएसइ मंडल,
घुघर।

(7) मंडी जिला :

जोगिन्दर नगर के चुहार वैली, बगरा के
थुनाग तहसील, छत्री छोटाधर, गरागुशैन,
गट्टू, गरयास, जनेली, जरियार, जोहर,
कल्हानी, कल्वान, खोलनाल, लोथ,
सिलीबागी, समाचान, तछदार, टची, ठाना,
बिंगा खण्ड का धरमपुर पंचायत करसोग
तहसील के बिंगा, कमलाह, सकलाना, तनयार
और तारखोला, सुन्दर नगर तहसील के
बलीधार, बगरा, गोपालपुर, खजौल, महोग,
मेंहुदी, मंज, पेखी, सेंज, सरहान और तेबान,
बोही, बटवारा, धनयारा। पौराकोठी, सेरी और
शोजा।

600/-

750/-

(8) सिरमौर जिला :

(क) बणी, बकहाली के पंचायत, (पछाड़
तहसील) बडोग, बनेरी (पोंटा तहसील),
बिडला (नहान तहसील) डिब्बर (पछाड़
तहसील) और ठाणा कसोगा (नहान
तहसील)

600/-

750/-

क्र. सं. स्थान, जहाँ भत्ता देय हो	देय भत्ते की दर	
	रु. 10,000/- से 14,000/- तक देय	रु. 14,001/- एवं उससे अधिक के लिए देय
(ख) थंसगिरी ट्रैक्ट		
(9) सोलन जिला मंगल पंचायत।	600/-	750/-
(10) हिमाचल प्रदेश के बाकी क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (9) अंदर शामिल नहीं है।	160/-	200/-
13. उत्तरप्रदेश : चमोली के क्षेत्र, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिले	1,000/-	1,300/-
2(क) पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिला के अन्य क्षेत्र (उत्तरकाशी जिला मुख्यालय सहित)		
2(ख) चंपावत जिला (लोहाघाट के क्षेत्र सहित)		
14. उत्तरांचल :		
रुद्रप्रयाग व चंपावत जिले के क्षेत्र	800/-	1,050/-

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च 2007 को तक दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के संलग्न तुलन-पत्र और दरगाह ख्वाजा साहब, अधिनियम, 1955 की धारा 19(1) के साथ पठित नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा कर ली है। लेखापरीक्षा वर्ष 2003-2004 से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों में दरगाह ख्वाजा साहब, के समस्त युनिटों के लेखे शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व दरगाह ख्वाजा साहब के प्रबन्धन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के सम्बन्ध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं अनियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के सम्बन्ध में वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त है योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना, रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार मुहैया करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत के लेखा महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित फार्मेट में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए लेखाओं की समुचित बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेख, जहां तक ऐसी बहियों के सम्बन्ध में हमारी जांच से प्रकट होता है, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि दरगाह ख्वाजा साहब, अधिनियम, 1955 की धारा-20(2)(डी) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :--

लेखों पर टिप्पणियां

ए. तुलन-पत्र

ए.1 दायित्व रु. 4.68/- करोड़

ए.1.1 प्रत्याभूत ऋण एवं उधार रु. 25.37/- लाख

इसे रु. 50,497/- से अधिक बताया गया है क्योंकि ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति की राशि को अनुसूची "अन्य चालू दायित्व" के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है। आवश्यक सुधार चालू वित्तीय वर्ष में कर दिए जाएंगे।

ए.1.2 ऋणों/उधारों पर ब्याज

दिनांक 31.3.2007 को उधार लिए गए द्वितीय एवं चतुर्थ ऋण पर प्रोदभूत ब्याज रु. 90,793/- के विरुद्ध रु. 60,384/- की राशि के ब्याज का भुगतान किया गया था। प्रोदभूत ब्याज की शेष राशि के दायित्व का लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप दायित्व को रु. 0.30/- लाख से कम बताया गया था तथा व्यय को भी उस सीमा तक कम बताया गया था।

दरगाह ने बताया कि सैन्ट्रल वक्फ कौन्सिल से माँग प्राप्त नहीं हुई थी, अतः लेनदारों में शामिल नहीं की गई थी तथा वास्तविक ब्याज हेतु प्रावधान करना सम्भव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखांकन मानक के अनुसार लेखे प्रोदभूत आधार पर संधारित किए जाते हैं। यदि प्रावधान सही रूप से नहीं बनाए जाते हैं तो दरगाह के लेखे सही स्थिति को नहीं दर्शाएंगे।

ए.2. परिसम्पत्तियां रु. 4.68 करोड़

ए.2.1 स्थाई परिसम्पत्तियां रु. 3.50 करोड़

(i) इन्हे 1.68 लाख से कम बताया गया है क्योंकि नये 9 टॉयलेटों का निर्माण कराया गया था परन्तु इनको पूंजीकृत नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप व्यय को रु. 1.68 लाख से अधिक बताया गया था।

दरगाह ने बताया कि पुरानी टॉयलेटों को तोड़ने के पश्चात् इनके नवीनीकरण कार्य पर व्यय किया गया था। इन 9 टॉयलेटों का निर्मित मूल्य पहले से ही स्थायी परिसम्पत्तियों में शामिल है अतः इसे राजस्व व्यय के रूप में माना गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुरानी टॉयलेटों को तोड़ने के पश्चात् व्यय किया गया है, और उसके बाद नई 9 टॉयलेटों का निर्माण किया गया था, जो कि पूंजीगत व्यय है।

(ii) एक मुश्त वाहन कर रु. 0.51 लाख का भुगतान किया गया था, परन्तु इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप स्थाई परिसम्पत्तियां कम बताई गई थी तथा व्यय को उस सीमा तक अधिक बताया गया था।

ए.2.2 चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि रु. 1.18 करोड़ प्राप्ति योग्य दावे :

इन्हें रु. 0.22 लाख से कम बताया गया है जो कि कम्प्यूटर उपभोज्य सामग्री जैसे फ्लोपियों, टोनर इत्यादि पर किए गए व्यय के कारण से था जो कि उर्दू-भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद् (एन.सी.पी.यू.एल.), माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य था, इस व्यय को “कम्प्यूटर सेन्टर व्ययों” के रूप में प्रभावित किया गया था। जबकि इसे दरगाह के तुलन-पत्र में एन.सी.पी.यू.एल. से प्राप्ति योग्य राशि के रूप में दर्शाया जाना था। यह व्यय के उस सीमा तक अधिक बताए जाने में भी परिणामित हुआ।

प्राप्ति योग्य दावों रु. 0.31 लाख पर समान टिप्पणियां वर्ष 2005-06 में भी की गई थी परन्तु वर्ष 2006-07 के लिए तुलन-पत्र में कोई प्रभाव नहीं दिया गया।

ए.2.3 स्टाफ अग्रिमों रु. 3.55 लाख को “अर्जित आय” के शीर्ष में दर्शाया गया जबकि इन्हें “स्टाफ को ऋणों एवं अन्य प्रतिभूति जमा” शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाना था।

तथ्य स्वीकार कर लिए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक सुधार कर लिए जाएंगे।

बी. आय एवं व्यय लेखा

बी.1 व्यय रु. 2.21 करोड़

बी.1.1 इन-साईड गुम्बद शरीफ व्यय रु. 5.82 लाख

पिछले वर्ष यह उल्लेख किया गया था कि 20.45 किलोग्राम लागत रु. 0.28 लाख के चन्दन के अन्तिम स्टॉक को लेखाओं में नहीं दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप, व्यय को अधिक बताया गया था तथा चालू परिसम्पत्तियों को कम बताया गया था। चालू वर्ष के दौरान, यह देखा गया कि रु. 1,74,750/- (रु. 184034/- अन्य व्यय रु. 9284.00/-) के मूल्य का चन्दन खरीदा गया था तथा रु. 25238/- के चन्दन का अन्तिम स्टॉक शेष रहा। इस प्रकार वर्ष 2004-05 के लिए रु. 27976/- के चन्दन के अन्तिम स्टॉक को शामिल करते हुए रु. 1,77,488/- मूल्य का चन्दन गुम्बद शरीफ में वर्ष 2006-07 के दौरान उपयोग में लिया गया था। जबकि उपभोग रु. 1,74,750/- (अन्य व्यय लेखे पर रु. 9284/- को छोड़ते हुए) का दर्शाया गया था। यह व्यय को रु. 0.03 लाख की सीमा तक कम बताए जाने में परिणामित हुआ।

बी. 2. आय

बी. 2.1 अर्जित आय

इसे रु. 2.26 लाख से कम बताया गया है जो कि वर्ष 2006-07 के दौरान सदस्यों और जायरीनों से कमरा किराया प्राप्त नहीं हुआ था, को लेखांकित नहीं किए जाने के कारण से हुआ। यह चालू परिसम्पत्तियों “ऋणों एवं अग्रिमों” के उस सीमा तक कम बताए जाने में भी परिणामित हुआ।

दरगाह ने बताया कि सदस्यों एवं जायरीनों से रु. 2.26 लाख की वसूली किए जाने की कोई आशा नहीं थी अतः इसे लेखाबद्ध नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि किराए की राशि दरगाह कमेटी द्वारा अपलिखित नहीं की गई है। अतः राशि को चालू परिसम्पत्तियों में दर्शाया जाना चाहिए था।

सी. सामान्य

दरगाह के लेखों की एक सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा की जा रही थी, जो कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा हाथ में लेने के लिए विहित मानक निबन्धनों एवं शर्तों का उल्लंघन था।

दरगाह ने बताया कि लेखापरीक्षा सी. ए. के द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षक के रूप में की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा सौंपे जाने के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार सी.ए.जी. के एक मात्र लेखापरीक्षक होने के कारण से किसी प्राथमिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति केवल सी.ए.जी. द्वारा ही की जा सकती है, जो कि सी.ए.जी. द्वारा जारी निर्देशनों एवं मार्गदर्शनों के आधार पर उनकी ओर से लेखापरीक्षा संचालित करेगा।

वर्ष 2005-06 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान टिप्पणी की गई थी।

सी. 2 अचल परिसम्पत्तियों, अर्थात् भवनों पर ह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

दरगाह ने बताया कि उसके एक धर्मार्थ न्यास होने के कारण से उसकी आय आयकर से मुक्त है। पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का धर्मार्थ संस्थान के व्यय के रूप में माना जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ह्रास के प्रावधान करने के अभाव में लेखे अचल परिसम्पत्तियों के सही एवं उचित मूल्य को प्रकट नहीं करते हैं।

वर्ष 2005-06 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान टिप्पणी की गई थी।

सी.3 किराए से आय तथा लीज राशि रु. 2.46 लाख को वर्ष के दौरान दरगाह कमेटी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही अपलिखित कर दिया गया है।

दरगाह ने बताया कि वर्ष 2006-07 के लिए लेखे लेखा समिति के द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपलिखित किराया आय एवं लीज राशि के लिए दरगाह कमेटी का विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

सी.4 जी-ब्लॉक में अतिथि गृह भवन के निर्माण एवं स्कूल के निर्माण हेतु रु. 8.50 लाख का दान प्राप्त हुआ था, लेकिन ऐसे अनुसूची “कॉरपस पूंजीगत निधि” के अन्तर्गत दर्शाया गया है जबकि इसे चिन्हित/बन्दोबस्ती निधि में दर्शाया जाना चाहिए था। क्योंकि निधियां किसी विशिष्ट चिन्हित प्रयोजन हेतु प्राप्त की गई थी।

दरगाह ने बताया कि चिन्हित/बन्दोबस्ती निधि को कॉरपस दान माना जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है लेखा के सामान्य फारमेट के अनुसार, कॉरपस पूंजीगत निधि (अनुसूची-1) तथा चिन्हित/बन्दोबस्ती निधि (अनुसूची-3) अलग-अलग होते हैं तथा तुलन-पत्र में पृथक् रूप से दर्शाए जाने चाहिए। टिप्पणियों के अनुसार निधियां विशिष्ट चिन्हित प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई थी जिन्हें अनुसूची-3 में चिन्हित/बन्दोबस्ती निधि में दर्शाया जाना चाहिए था।

सी.5 अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित बैंक में रु. 89,00,000/- का निवेश किया गया। इसे बैंक शेष की अनुसूची-11 में दर्शाया गया है, जबकि इसे अनुसूची-10 “निवेश अन्य” में दर्शाया जाना था।

दरगाह ने बताया कि स्थाई जमा बैंक शेष का ही एक भाग होता है अतः इसे अनुसूची-11 में दर्शाया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। लेखाओं के सामान्य फारमेट के अनुसार, एफ.डी.आर. को “सरकारी प्रतिभूतियां अनुसूची-10, निवेश-अन्य” में दर्शाया जाना चाहिए था।

सी.6 स्टॉफ की अंशदायी निधि

दरगाह ख्वाजा साहब के पास रु. 6432393.52 पड़े हुए थे जिन्हें तुलन-पत्र में दायित्व पक्ष की ओर तथा साथ ही साथ परिसम्पत्ति पक्ष की ओर शेड्यूल-9 में नहीं दर्शाया गया है।

दरगाह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक सुधार करे जाएंगे।

सी.7 लेखाओं के साथ अनुसूची-24 के रूप में संलग्न महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति इंगित करती है कि :-

- (i) कर्मचारियों की मृत्यु/सेवा निवृत्ति पर भुगतान योग्य ग्रेज्युटी का दायित्व वास्तविक मूल्यांकन पर प्रोदभूत होता है।
- (ii) कर्मचारियों को संचित छुट्टियों के नकदीकरण हितलाभ के लिए प्रावधान प्रोदभूत आधार पर बनाया जाता है तथा इस पूर्व-मान्यता के आधार पर परिकलित किया जाता है कि कर्मचारी इस हितलाभ के प्रत्येक वर्ष के अन्त में हकदार

होते हैं। अभिलेखों की संवीक्षा किए जाने पर यह पाया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा लेखाओं में अनुसूची-7 “चालू दायित्व एवं प्रावधान” के अन्तर्गत नहीं दर्शाया गया है।

दरगाह ने बताया कि तुलन-पत्र में ग्रेच्युटी तथा छुट्टी नकदीकरण के शेषों को दर्शाया जाना संभव नहीं है। अनुसूची-24 के रूप में लेखाओं के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के मध्य-नजर उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

सी.8 दरगाह शरीफ के लिए दान के रूप में प्राप्त हुए रु. 0.17 लाख के मूल्य के 10 रजत बाउन्स की स्टॉक-प्रविष्टि नहीं थी। इनका कब्जा भी प्रबन्धन के पास होना नहीं पाया गया था। दरगाह ने बताया कि ये रजत-बाउन्स दरगाह शरीफ में लटके हुए हैं। ये दरगाह की तिजोरी में नहीं हैं, अतः इन बाउन्स की लागत को वर्ष 2006-07 के लिए लेखाओं में व्यय के रूप में पुस्तकांकित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, लेखांकन प्रैक्टिसों के अनुसार, माल/वस्तु के रूप में प्राप्त हुए दान को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाए ताकि वित्तीय प्रास्थिति की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

डी. प्रबन्धन-पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियां उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबन्धन पत्र के माध्यम से प्रबन्धन की सूचना में लाई गई है।

(v) उपर्युक्त पैराओं में हमारी अभ्युक्तियों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन-पत्र/आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा-बहियों के अनुरूप है।

(vi) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबन्ध-1 में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं :--

ए. जहां तक यह 31 मार्च 2007 को दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के कार्यों के तुलन-पत्र से संबंधित है।

बी. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष से संबंधित है।

ई. लेखाओं पर लेखापरीक्षा का प्रभाव :

उपर्युक्त पैराओं में दी गई टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह रहा कि 31 मार्च 2007 को परिसम्पत्तियां रु. 4.95 लाख से कम बताई गई है, दायित्व रु. 2.56 लाख से कम बताए गए हैं तथा व्यय पर आय के आधिक्य को रु. 2.39 लाख से कम बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए

स्थान-जयपुर

दिनांक 31.12.2008

ह./-

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा)

राजस्थान, जयपुर।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुबन्ध-1

1. आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में पर्याप्तता :

दरगाह में अपनाई जा रही आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है। कथित आन्तरिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) केवल अन्तिम लेखे तैयार करते हैं तथा इनकी केवल जांच करते हैं।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में पर्याप्तता :

दरगाह में अपनाई जा रही आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को लेखापरीक्षा के दौरान मूल्यांकित किया गया था तथा निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई :--

(I) सामान्य

- (i) रोकड़, स्टॉक एवं अन्य मूल्यांकन मदों से संबंधित कर्मचारियों के कर्तव्यों के रोटेशन की कोई योजना नहीं है।
- (ii) दरगाह में खादियों के कार्यों को विनियमित करने के लिए उनको लाईसेंस तैयार करने एवं जारी करने का कोई सिस्टम नहीं है।

(iii) देगों में जायरीनों के द्वारा डाली गई धनराशि पर कोई नियंत्रण नहीं है।

(iv) सलाहकार समिति, जैसा कि दरगाह ख्वाजा साहब, अधिनियम की धारा-10 में वर्णित है, का अभी तक गठन नहीं किया गया है।

(II) रोकड़ तथा बैंक

संस्था में कई प्रकार की रसीद पुस्तकें हैं। कम्प्यूटर सेन्टर रसीद-पुस्तकें तथा ख्वाजा मॉडल स्कूल रसीद पुस्तकें क्रमशः उनके स्वयं के द्वारा छपवाई जाती हैं। सभी रसीदों की मॉनीटरिंग के लिए केवल एक ही प्रकार की रसीद बुक छपवाई जानी चाहिए।

- (i) उपयोग रहित रसीद-बुकें स्टोर कीपर के बजाए रोकड़िए के कब्जे में हैं।
- (ii) उपयोग रहित रसीद-बुकों की वास्तविक जांच निष्पादित नहीं की जा रही है।

(III) क्रय एवं विक्रय

- (i) क्रयों को केन्द्रीयकृत नहीं किया गया है।
- (ii) सामग्री/आपूर्ति आदि केन्द्रीय स्टोर की बजाए विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त की जाती है।
- (iii) क्रय आदेश रजिस्टर, जिसमें प्रारम्भ से अन्त तक प्रत्येक क्रय का विवरण रखा जाता है, संधारित नहीं किया जा रहा है।

(IV) स्थाई परिसम्पत्तियां

- (i) सम्पत्ति को अद्यतन नहीं किया गया था रजिस्टर में चल परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया गया था। रजिस्टर के अंकों का लेखाओं से मिलान नहीं किया जाता है।
- (ii) इस बात को प्रमाणित करने का कोई सिस्टम नहीं है कि समस्त सम्पत्तियां संस्था के कब्जे में हैं और कोई अतिक्रमण नहीं है।
- (iii) प्रत्यक्ष-सत्यापन के लिए कोई लिखित कार्य-विधि नहीं है।
- (iv) भवनों का आग, दंगे तथा सिविल उपद्रव इत्यादि के विरुद्ध बीमा नहीं कराया गया है।

V. स्टॉक

कच्चे माल जैसे चीनी, चावल, गेहूं, चन्दन इत्यादि का न्यूनतम एवं अधिकतम स्टॉक-स्तर रखे जाने के लिए इनके स्टॉक-स्तर के लिए कोई मानक तय नहीं किए गए हैं।

एस. के. भार्गव
वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.सी.-I

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2007-08**दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर ।**

यह मेरा सोभाग्य है के मैं दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के प्रशासन पर अपने कार्यकाल की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट बराये साल 2007-08 पेश कर रहा हूँ ।

यह वर्ष घटनाओं से भरा वर्ष रहा जिसमें कम्यूनिटी सेवाओं एवं ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती (र.अ.) का मिशन मुख्य ध्येय था । वर्ष के दौरान दरगाह कमेटी में भी बदलाव हुआ ।

ए. प्रबंधन

भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन संख्या: एस.ओ.1456(ई) दिनांक 24.08.2007 के द्वारा निम्न व्यक्तियों को दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर का सदस्य नियुक्त किया ।

i.	जनाब नवाब मोहम्मद अब्दुल अली साहब,	चेन्ई ।
ii.	जनाब हाजी हाफिज वकील अहमद साहब,	सुलतानपुर ।
iii.	जनाब मोहम्मद इलियास कादरी साहब	अजमेर।
iv.	जनाब प्रोफेसर (डॉ) इब्राहीम साहब,	दिल्ली ।
v.	जनाब प्रोफेसर सोहेल अहमद खान साहब,	पटना ।
vi.	जनाब ए.एच. खान चोधरी साहब,	दिल्ली ।
vii.	जनाब एम.एस.एम तिरमीजी,	अहमदाबाद ।
viii.	जनाब बदरुद्दीन जी शेख साहब,	अहमदाबाद ।
ix.	जनाब घोले इस्माईल मुअल्लिम साहब,	रायगढ़ ।

दरगाह कमेटी अजमेर द्वारा दी जाने वाली खिदमात ।

1. मजार मुबारक पर रोजाना फूल, संदल एवं मोमबत्तियाँ पेश करना ।
2. माह शव्वाल में हजरत ख्वाजा उस्मान हारुनी (र.अ.) के उर्स का इतेजाम ।
3. अंदरुन दरगाह शरीफ की में मुहर्रम शरीफ का इतेजाम ओर चिल्ला हजरत बाबा फरीद (र.अ.) को खुलवाना ।
4. खुल्फा-ए-राशिदेन ओर बुजुर्गाने दीन की फातिहा कराना ।
5. दीनी तालीम के लिये दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का संचालन ।
6. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ख्वाजा माडल स्कूल का संचालन (अग्रेजी माध्यम की स्कूल) जिसमे धार्मिक ओर नेतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है ।
7. गरीब नवाज कम्प्यूटर सेन्टर का प्रबंधन ।
8. माहे रमजान में प्रतिदिन खास लंगर के जरिये सहर ओर अफतार का प्रबंध ।
9. बेवाओं ओर जरुरतमंदों को वजीफा ।

10. यूनानी दवाखाने का प्रबंधन एवं दवाईयों का निःशुल्क वितरण ।
11. मेडीकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी कोर्सेस के लिये छात्रवृत्ति ।
12. ईदगाह का प्रबंधन एवं अन्य मस्जिदों की वित्तीय सहायता ।
13. लावारिस मययूतो का निःशुल्क कफन दफन ।
14. दरगाह में स्वच्छ पीने के पानी का इंतजाम ।
15. वजू के लिये साफ पानी का इंतजाम ।
16. उर्स एवं अन्य धार्मिक उत्सवों के दौरान शामियानों का इंतजाम ।
17. मोरूसी अम्ले को तनख्वाह (हकूक) की अदायेगी ।
18. राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम ।

1. वर्ष 2007-2008 में किये गये प्रोजेक्ट्स / कार्य ।

दरगाह कमेटी का मुख्य ध्येय “जायरीन की सेवा” मुलभूत विकास के जरिये एवं सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती (र.अ.) की शिक्षाओं का विस्तार करना है । इस ध्येय को पाने के लिये यह आवश्यक है कि निरंतर हर तरफ प्रयास जारी रहें । दरगाह कमेटी ने इसके लिये निम्न प्रोजेक्ट्स को फरवरी 2007 से जनवरी 2008 तक लिया है ।

- ❖ सुरक्षा ।
- ❖ उर्स एवं उत्सवों का प्रबंधन ।
- ❖ जायरीन को सुविधायें ।
- ❖ प्रशासन ।
- ❖ स्टाफ वेल्फेयर ।
- ❖ वित्त ।
- ❖ शिक्षा ।
- ❖ योजना ।

2. उर्स एवं अन्य धार्मिक उत्सवों का प्रबंधन :

795 वॉ उर्स जुलाई 2007 में सम्पन्न हुआ जिसमें 6 लाख जायरीन ने गुम्बद मुबारक की जियारत की । उर्स दुर्घटना विहीन रहा जिसमें जायरीन को मुलभूत सुविधायें दरगाह कमेटी की जानिब से दी गई । इन व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया । कई हस्तियाँ जिसमें महामहिम राज्यपाल, राजस्थान एवं हरयाणा ने भी जियारत की ओर अपनी अकीदत का नजराना पेश किया ओर उर्स में अच्छे इंतजामात को सराहा ।

दरगाह कमेटी ने मिनी उर्स (मुहर्रम) के भी इंतजामात किये जो कि जनवरी 2008 में मनाया गया जिसमें सुरक्षा ओर सुविधायें एजेण्डे में सर्वोपरी थीं ।

3. दरगाह जायदाद / धर्मान्दा का विकास एवं संरक्षण:

दरगाह धर्मान्दा के नियमित विकास / मंटीनेन्स के अलावा दरगाह जायदादों का संरक्षण भी जरूरी है ताकि जायरीन उनका उपयोग कर सकें। दरगाह की आय बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि जायदादों का विकास किया जाये ताकि उन्हें किराये पर दिया जा सके। कानूनी मामलात अन्य मसला है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। दरगाह कमेटी ने इन सभी कार्यों पर प्रयास किये जो कि निम्न हैं:-

1. दरगाह की जायदादों की कीमत का आन्तरिक तख्मीना निकाला गया।
2. दरगाह शरीफ में अनाधिकृत कब्जेधारियों का सर्वेक्षण (मुबायना) किया गया ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। उक्त सर्वेक्षण बहुत ही संवेदनशील एवं जोखिम भरा कार्य था जोकि अर्द्धरात्रि के समय किया गया।
3. प्रथम बार दरगाह शरीफ का नक्शा तैयार किया गया।
4. 11 माह के अंतराल में 20 अदद जायदादों का कब्जा लेने में सफलता पाई जो कि अनाधिकृत कब्जेधारियों के कब्जे में थी।
5. कानूनी लड़ाई के बाद ईदगाह के लेवल का कार्य किया एवं चिल्ला कुतुब साहब पर लगभग 2700 स्क/फीट भूमि का कब्जा लिया जो कि जायरीन / आम पब्लिक के उपयोग के लिये विकसित की जायेगी।
6. चिल्ला कुतुब साहब पर अनाधिकृत कब्जेधारियों से अतिक्रमण को हटाया एवं लगभग 2700 स्क/फीट भूमि का कब्जा लिया जो कि अजमेर शहर की महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है।
7. मध्यप्रदेश ओर राजस्थान के कई शहरों का भ्रमण किया ताकि अनाधिकृत कब्जेधारियों से कृषि भूमि जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये होती है, को छुड़ाने की कार्यवाही की जा सके। उक्त मामलात कानूनी कार्यवाही के तहत विचाराधीन है।
8. पानी की कमी अजमेर शहर एक खास समस्या है। दरगाह शरीफ में पानी का स्रोत एक मात्र झरना है जो कि झालरा कहलाता है। माह फरवरी 2007 में इस झरने में पानी का लेवल 3.5 फीट था। पानी की समस्या को हल करने एवं ऐतिहासिक भूगर्भित जल के संरक्षण के लिये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। परिणामस्वरूप अब पानी का जलस्तर 24.5 फीट है जो कि नेट 21 फीट की बढ़ोतरी है।
9. दरगाह परीसर में ऐतिहासिक सेहन चिराग का पुनःउद्धार किया गया।
10. वार्षिक उर्स जुलाई 2007 के दौरान अहाता-ए-नूर, आस्ताना शरीफ के अगले भाग, के दो मार्बल के दरवाजे जो कि बाब-ए-कादरिया एवं बाब-ए-आवेसिया कहलाते हैं तकनीकी कारणों से हिलने लगे थे ओर सुरक्षा की दृष्टि से जायरीन के लिये खतरा बन सकते थे की मरम्मत के लिये मुम्बई दक्ष वास्तुविद एवं कुशल कारीगरो की सेवायें ली गई एवं दरवाजों को मुगल वास्तुकला के अनुसार संरक्षित किये गये।

11. मस्जिद संदल खाना (एक ऐतिहासिक मस्जिद जो कि आस्ताना शरीफ के पास स्थित है) का संदला / प्लास्टर जो कि काफी पुराना था ओर भददा लग रहा था उसके स्थान पर मार्बल लगाया जा चुका है ।
12. इसी तरह अकबरी मस्जिद (एक ऐतिहासिक मस्जिद जो कि आस्ताना शरीफ के पास स्थित है))के पश्चिम का केन्द्रीय हिस्सा जो कि प्लास्टर उखड़ने के कारण काफी भददा लग रहा था । उसके स्थान पर मार्बल लगा दिया गया है ।

4. जायरीन के लिये सुविधायें:

झालरा में पानी के लिये 19 फीट ऊँचाई पर बनी टंकी एवं आधुनिक फिल्टर प्लान्ट से जायरीन को 24 घंटे पीने के पानी की सुविधा है । नई पाईप लाइन जो कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से पानी लेकर पानी की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जाता है ।

1. दरगाह परीसर में 24 घंटे वजू के लिये पानी की सप्लाई ।
2. सर्दी में गर्म एवं गर्मी में ठण्डे पानी की व्यवस्था ।
3. वक्तन-फवक्तन गरीब नवाज गेस्ट हाउस का पुनःउद्धार । गर्म पानी की सप्लाई के लिये आधुनिक 1500 लीटर क्षमता का एक बायलर लगाया गया ।
4. विद्युत सप्लाई बन्द होने पर आधुनिक जेनेरेटरों द्वारा निर्बाध विद्युत सप्लाई की व्यवस्था ।
5. शामियानों की व्यवस्था ताकि जायरीन को धूप, गर्मी एवं सर्दी से बचाया जा सके । स्थाई शामियानों की व्यवस्था हेतु प्राजेक्ट विचाराधीन है ।
6. भारत सरकार, पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय एवं अजमेर जिला प्रशासन, राजस्थान सरकार के समर्थन से विश्राम स्थली का कार्य जोर शोर से प्रगति पर है । विश्राम स्थली बनाने का उद्देश्य दरगाह ख्वाजा साहब के जायरीन को सुविधायें देना है । कई राज्यों की सरकारों ने अपने राज्य के जायरीन के लिये स्टेट पेवेलियन बनाने में रुचि दिखाई है । इस प्रोजेक्ट के तहत 60 हजार जायरीन एवं 5 हजार बसे एक साथ पार्क की सकती हैं । विश्राम स्थली का प्रशासनिक भवन सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा करीब पूरा किया जा चुका है । राष्ट्रीय राज मार्ग 8 से विश्राम स्थली के लिये मार्ग धन के अभाव में लंबित है ।
7. यूनानी एवं होम्योपैथिक दवाखानों को ओर चाक चोबंद बनाया जायेगा जिसके लिये कई स्वयं सेवी एवं एन.जी.ओ. से जो कि चिकित्सा सुविधा देने में रुचि दिखा रहे हैं से बातचीत जारी है ।
8. दरगाह शरीफ के क्षेत्र में जायरीन के लिये शोच आदि की समस्या से निबटने के लिये एक प्रस्ताव अजमेर नगर परिषद को त्रिपोलिया गेट के पास शोचालय बनाने हेतु भेजा गया है ।

9. एक भूमि का टुकड़ा झालरा के पास सुलभ ब्लॉक बनाने के चिन्हित किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहिले उक्त भूमि का विकास जरूरी है।
10. ईदगाह में जायरीन / आम पब्लिक के लिये जगह को दुगुना कर दिया गया है।

5. प्रशासन:

1. दरगाह कमेटी एंव सज्जादानशीन, खुद्दाम एंव जायरीन में सोहाद्रपूर्ण वातावरण तैयार बनाया गया है।
2. वेबसाईट का बनाना ताकि कमेटी की तरफ दानदाताओं का रुझान बढ़े।
3. कर्मचारी जो कि लम्बे समय से एक विभाग में कार्यरत थे उनका स्थानान्तरण करके अधिकतम मानव श्रमता का इस्तमाल करना।
4. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को लागू करना।
5. विधवा पेंशन, जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिये प्रोफोर्मा बनाना। इस प्रकार की वित्तीय सहायता दरगाह कमेटी द्वारा दी जाती है।
6. अवकाश एंव निजी रिकार्ड्स का संधारण।
7. दरगाह के खातों का कम्प्यूटरीकरण।
8. अतिथिगृह को भी जल्द ही कम्प्यूटरीकृत करना।

6. वित्त:

नीचे दर्शाई गई सारणी दरगाह समिति की आय एंव खर्च की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करती है।

दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर।			
पूर्व वित्तीय वर्ष			चालू वित्तीय वर्ष
651598	ओपनिंग बैलेंस 01.04.2008		472396
27804344	अनुमानतः आय बराये वर्ष 2008-09		33781700
28455942	कुल		34254096
	अनुमानतः खर्च बराये वर्ष 2008-09		
23674257	रेवेन्यू खर्च		29407000
1009289	कैपिटल खर्च		1500000
24683546			30907000
472396	क्लोसिंग बैलेंस 31.03.2009		3347096
8900000	एफ.डी.आर. 01.04.2007		
12200000	एफ.डी.आर. 31.03.2008		

एफ. दरगाह कमेटी की बैठके :

वर्ष के दौरान दरगाह कमेटी की पाँच बैठकें दरगाह के मामलात के संबध में आयोजित हुई ।

जी. वी.वी.आई.पी. एवं वी.आई.पी. का आगमन :

निम्नलिखित अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने दरगाह शरीफ की जियारत की जिसका की उल्लेख निम्न प्रकार है ।

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. श्री ए.आर किदवाई साहब, | महामहिम राज्यपाल राजस्थान एवं हरयाणा । |
| 2. श्रीमती वसुन्धरा राजे जी, | मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार । |
| 3. श्री लालजान बाशा साहब, | अध्यक्ष, संयुक्त संसदीय समिति । |
| 4. श्री सुजीत दत्ता जी, | सांसद एवं संयुक्त सचिव, भारत सरकार । |
| 5. श्री मेहमूद अख्तर साहब, | उप सचिव, भारत सरकार । |
| 6. श्री लालू प्रसाद यादव, | रेल मंत्री, भारत सरकार । |
| 7. श्री चन्द्र बाबू नायडू, | पूर्व मुख्य मंत्री, ए.पी. । |
| 8. श्री डाक्टर शकील अहमद, | मंत्री, आई टी एवं दूरसंचार, भारत सरकार । |

एच. लेखों का अंकेक्षण

दरगाह के लेखों एवं रिकार्ड्स का अंकेक्षण बराये साल 2006-07 प्रिसिपल अकाउण्टेन्ट जनरल, राजस्थान जयपुर की टीम ने किया । ऑडिट 5 फरवरी 2008 से 19 फरवरी 2008 किया गया । कुछ सुझाव जो के सामान्य प्रकृति के थे आडिट ने दिये जिसकी पालना से कार्य में ओर बेहतरी आयेगी ।

आई. धन्यवाद

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तमाम दरगाह कमेटी के सदस्यों का मैं आभारी हूँ जिनके दिये गये मार्गदर्शन से दरगाह शरीफ का प्रबंधन सुचारु रूप से हो पाया । दरगाह कमेटी के सहयोग के परीणाम स्वरूप नित प्रति दिन एवं उर्स एवं मुख्य दरगाह शरीफ की रसूमात का प्रबंधन बिना किसी व्यवधान के हुआ ।

मैं अपने कर्तव्यों में असफल रहता यदि मुझे अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन अजमेर, पुलिस विभाग, नगर परिषद, विद्युत विभाग एवं अन्य विभागों से निरन्तर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता जिससे दरगाह प्रशासन में गुणवत्ता आई ।

मैं यहाँ अपनी रिपोर्ट इस नोट के साथ खत्म करता हूँ के आने वाला वर्ष भी चुनोतीपूर्ण होगा जिससे मैं निर्माण कार्य व कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जायेगा जिसके लिये एक खाके (Vision Document) की तैयारी प्रगति पर है ।

अहमद रज़ा
नाजिम एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब,
अजमेर

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

हमने 31 मार्च 2008 तक दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के संलग्न तुलन-पत्र और दरगाह ख्वाजा साहब, अधिनियम 1955 की धारा 19 (1) के साथ पठित नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा कर ली है। लेखापरीक्षा वर्ष 2003-2004 से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों में दरगाह ख्वाजा साहब, के समस्त युनितों के लेखे शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व दरगाह ख्वाजा साहब के प्रबन्धन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के सम्बन्ध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं अनियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के सम्बन्ध में वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना, रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार मुहैया करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :--

(i) हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत के लेखा महानियंत्रक लेखा द्वारा अनुमोदित फार्मेट में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए लेखाओं की समुचित बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेख, जहां तक ऐसी बहियों के सम्बन्ध में हमारी जांच से प्रकट होता है, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि दरगाह ख्वाजा साहब, अधिनियम, 1955 की धारा-20(2)(डी) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :--

लेखों पर टिप्पणियां

ए. तुलन-पत्र

ए.1 दायित्व रु. 6.05/- करोड़

प्रतिभूत ऋण एवं उधार रु. 0.19/- करोड़

प्रोद्भूत ब्याज-ऋणों/उधारों पर

II, III, IV ऋण (केन्द्रीय वक्फ परिषद् नई दिल्ली से प्राप्त) पर ब्याज का भुगतान क्रमशः 16.12.2007, 17.03.2008 तथा 14.02.2008 तक का किया गया था परन्तु 31.03.2008 तक देय ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप दायित्व रु. 0.18 लाख से कम बताए गए थे तथा व्यय भी उस सीमा तक कम बताया गया था।

ए. 2 आस्तियां रु. 6.05 करोड़

(i) रु. 0.20 लाख का एक मुश्त वाहन कर का भुगतान किया गया था परन्तु उसे पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्थाई आस्तियों को कम बताया गया था तथा व्यय उस सीमा तक अधिक बताया गया था।

वर्ष 2006-07 के प्रतिवेदन में भी रु. 0.51 लाख की समान टिप्पणी शामिल की गई थी, परन्तु लेखाओं में इस बाबत कोई प्रभाव नहीं डाला गया।

(ii) इसे रु. 0.51 लाख से कम बताया गया था, क्योंकि निर्माण कार्य रु. 3.51 लाख का कराया गया था, परन्तु बहियों में केवल रु. 3.00 लाख ही लेखांकित किए गए थे। प्रतिभूति जमा की राशि तथा बिल में से कटौती कर रोकी गई 10% राशि को दायित्व के रूप में दर्शाया नहीं गया था। इसके परिणामस्वरूप रु. 0.51 लाख से दायित्व भी कम बताए गए थे।

(iii) यह रु. 5.09 लाख से अधिक बताए गए हैं, क्योंकि ख्वाजा मॉडल स्कूल का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था। अतः “कार्य प्रगति में” उस सीमा तक कम बताए गए थे।

(iv) यह रु. 1.68 लाख से कम बताए गए हैं, क्योंकि नए 9 टॉयलेटों (सुविधाओं) का निर्माण कराया गया था, परन्तु इन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यय रु. 1.68 लाख से अधिक बताए गए थे।

वर्ष 2006-07 में भी यह टिप्पणी दर्ज की गई थी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

ए. 3 चालू आस्तियां-ऋण एवं अग्रिम इत्यादि रु. 1.62 करोड़

(i) यह रु. 0.30 लाख से कम बताए गए हैं, जिसका कारण कम्प्यूटर उपभोज्य सामग्री जैसे प्लॉपी, टोनर इत्यादि पर किया गया व्यय है जो उर्दूभाषा उन्नयन के लिए राष्ट्रीय परिषद् (एन.सी.पी.यू.एल.), माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से पुर्नभरण प्राप्त किए जाने के योग्य था, परन्तु इस राशि को एन.सी.पी.यू.एल. से प्राप्ति योग्य दर्शाए जाने के बजाए आय-व्यय खाते में कम्प्यूटर सेन्टर व्ययों के रूप में प्रभारित किया गया था। यह उस सीमा तक व्यय के अधिक बताए जाने में भी परिणामित हुआ।

वर्ष 2006-2007 में भी रु. 0.22 लाख के प्राप्ति योग्य दावों के बाबत भी समान टिप्पणियां शामिल की गई थी परन्तु वर्ष 2007-08 के तुलन पत्र में इस बाबत कोई प्रभाव नहीं डाला गया था।

(ii) यह रु. 2.79 लाख से कम बताए गए हैं, जो कि विद्युत कनेक्शन हेतु पिछले वर्षों में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर में जमा कराई गई प्रतिभूति की राशि बाबत हैं परन्तु इसे “चालू-आस्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों” में नहीं दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत-निधि भी उस सीमा तक कम बताई गई थी।

(iii) यह रु. 0.045 लाख से कम बताए गए हैं, क्योंकि माध्यमिक स्कूलों की परीक्षाओं को अवधि 1.04.2008 से 31.03.2011 तक के लिए सम्बद्धता हेतु भुगतान किए गए अग्रिमों को “ऋणों एवं अग्रिमों” में नहीं दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऋण एवं अग्रिम कम बताए गए थे तथा उस सीमा तक व्यय अधिक बताए गए थे।

बी. आय एवं व्यय लेखा

बी. 1 व्यय रु. 2.49 करोड़

(i) व्यय रु. 1.03 लाख से अधिक बताए गए हैं, क्योंकि चल आस्तियों जैसे दरी गदेला, रजाईयों इत्यादि को आय एवं व्यय खातों में बुक कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप आस्तियां भी इस सीमा तक कम बताई गई थी।

(ii) यह रु. 0.33 लाख से अधिक बताया गया है, क्योंकि दरगाह कमेटी द्वारा भुगतान किया गया कर्मचारी राज्य बीमा के लिए कर्मचारियों का अंशदान संबंधित कर्मचारी से वसूल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू आस्तियां भी उस सीमा तक कम बताई गई थी।

(iii) यह रु. 5.97 लाख से अधिक बताए गए हैं, क्योंकि उपकरण/इलेक्ट्रॉनिक मद सुरक्षात्मक उपायों के लिए क्रय किए गए थे, परन्तु पूंजीकृत नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप स्थाई आस्तियां भी उस सीमा तक कम बताई गई थी।

(iv) यह रु. 2.37 लाख से अधिक बताए गए हैं, क्योंकि चिल्ला कुतुब साहब की साईट पर भूमि को विकसित करने, समतल एवं सफाई करने पर किए गए व्यय को पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप आस्तियां उस सीमा तक कम बताई गई थी।

(v) यह रु. 1.74 लाख से अधिक बताया गया है, क्योंकि नया गेट लगाने तथा ईदगाह सब्जी मण्डी पर स्थल को समतल करने पर किए गए व्यय को पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्थायी आस्तियों को भी उस सीमा तक कम बताया गया था।

बी. 2 आय रु. 2.57 करोड़

(iii) यह रु. 2.26 लाख से कम बताए गए हैं, क्योंकि जिसका कारण वर्ष 2006-07 के दौरान सदस्यों/जायरीनों से प्राप्त नहीं हुए कमरे के किराए को लेखाओं में दर्ज नहीं किया जाना था। यह उस सीमा तक चालू आस्तियों "ऋणों एवं अग्रिमों" को कम बताए जाने में भी परिणामित हुआ। इसे वर्ष 2006-07 में भी सूचित किया गया था, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सी. सामान्य

1. दरगाह के लेखा सनदी लेखकार फर्म द्वारा लेखा-परीक्षित किए जा रहे थे जो नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में विहित मानक निबंधनों एवं शर्तों (शर्तें) का उल्लंघन था।

वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान टिप्पणी की गई थी। 2(i) अचल सम्पत्तियों, अर्थात् भवनों पर हास प्रभारित नहीं किया गया है।

वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान टिप्पणी की गई थी।

(ii) वर्ष के दौरान क्रय की गई चल आस्तियों पर भी आनुपातिक (प्रो-रेटा) आधार पर हास प्रभारित नहीं किया गया था।

3. वर्ष के दौरान रु. 0.21 लाख की किराए से आय एवं लीज राशि दरगाह कमेटी के अनुमादेन बिना अपलेखित कर दी गई है।

वर्ष 2006-07 के प्रतिवेदन में भी राशि रु. 2.46 लाख की समान टिप्पणी शामिल की गई थी, परन्तु अपलेखन के लिए दरगाह कमेटी का अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं किया गया था।

4(i) चन्दन फण्ड के लिए रु. 1.00 लाख का दान प्राप्त किया गया था, जिसे चिन्हित/बन्दोबस्ती निधियों की बजाय "कोरपस केपीटल फण्ड" में दर्शाया गया था, क्योंकि फण्ड विशेष प्रयोजन हेतु प्राप्त किया गया था।

(ii) "जी" ब्लॉक में अतिथि गृह भवन तथा स्कूल के निर्माण के लिए रु. 8.50 लाख का दान वर्ष 2006-07 के दौरान प्राप्त किया गया था, परन्तु क्योंकि फण्ड किसी विशिष्ट चिन्हित प्रयोजन के लिए प्राप्त किया गया था, अतः इसे चिन्हित/बन्दोबस्ती निधि के बजाए "कोरपस केपीटल फण्ड" अनुसूची के तहत दर्शा दिया गया था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 में टिप्पणी इंगित की गई थी, परन्तु कोई उपचारी कार्यवाही नहीं की गई थी।

(iii) रु. 1.22 करोड़ का निवेश अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित बैंक में किया गया था। इसे अनुसूचि-10, निवेश एवं अन्य में शामिल किए जाने के बजाए अनुसूचि-11 में बैंक शेष में शामिल कर लिया गया था।

यह टिप्पणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 में इंगित की गई थी, परन्तु कोई उपचारी कार्यवाही नहीं की गई।

5. लेखाओं के साथ अनुसूची-24 के रूप में संलग्न की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति दर्शाती है कि:--

(i) कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर भुगतान के योग्य ग्रेच्युटी के दायित्व को जीवन संभावना बीमांकिक दायित्व (actuarial) के आधार पर उपाजित होना आवश्यक है।

(ii) कर्मचारियों को संचित अवकाश नकदीकरण हितलाभ का प्रावधान अर्जित होता है तथा इस पूर्व मान्यता पर संगणित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अन्त में इन लाभों को प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

रिकार्ड की संवीक्षा पर यह पाया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा “चालू दायित्वों एवं प्रावधानों” की अनुसूची-7 के तहत लेखाओं में दर्शाए नहीं गए हैं।

6. दरगाह शरीफ में दान के रूप में प्राप्त हुए रु. 0.17 लाख के मूल्य के 10 संख्या में चांदी के बाउल्स की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं थी। इनका कब्जा भी प्रबन्धन के पास होना नहीं पाया गया था।

यह टिप्पणी वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इंगित की गई थी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

7. राजस्थान सरकार ने अजमेर जिले में जूनिया गोंव में 0.56 हैक्टर भूमि आवंटित की है, परन्तु अनुसूची ए-1 में इसे 0.46 हैक्टर दिखाया गया है।

लेखाओं पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव:--

पिछले पैराओं में दी गई टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह हुआ है कि 31 मार्च 2008 को आस्तियां रु. 19.96 लाख से कम बताई गई हैं, दायित्व रु. 3.48 लाख से कम बताए गए हैं तथा व्यय पर आय के अधिक्य को रु. 16.48 लाख से कम बताया गया है।

डी. प्रबन्धन-पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियां उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक् रूप से जारी प्रबन्धन पत्र के माध्यम से प्रबन्धन की सूचना में लाई गई हैं।

v. पिछले पैराओं में हमारी अभ्युक्तियों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाकरण नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबन्ध-1 में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:--

क. जहां तक यह 31 मार्च 2008 को दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के कार्यों के तुलन-पत्र से सम्बन्धित है।

ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के आधिक्य से सम्बन्धित है।

(vii) ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 06.04.2009 को जारी की गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 08.06.2009 को अनुस्मारक जारी किया गया था, परन्तु अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इसमें उल्लिखित टिप्पणियां सत्यापित मानी जाती हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए

स्थान-जयपुर

दिनांक 18.08.2009

ह./-

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा)

राजस्थान, जयपुर।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुबन्ध-1

1. आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

दरगाह में प्रचलित आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है। कथित आन्तरिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) केवल अन्तिम लेखाओं की जांच एवं इन्हें तैयार करता है।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पूर्णता :

लेखापरीक्षा के दौरान दरगाह में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण-प्रणाली का मूल्यांकन किया गया तथा निम्नलिखित स्थिति सामने आई :--

3(i) सामान्य

(i) रोकड़, स्टॉक एवं अन्य मूल्यवान मदों पर लगे हुए कर्मचारियों के कर्तव्यों के रोटेशन की कोई योजना मौजूद नहीं है।

(ii) खादिमों को उनके दरगाह में कार्यों को विनियमित करने के लिए लाईसेंस तैयार करने एवं जारी करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है।

(iii) जायरीनों द्वारा देगों में डाली जाने वाली धनराशि पर कोई नियंत्रण मौजूद नहीं है।

(iv) सलाहकार समिति, जैसा कि दरगाह ख्वाजा साहब, अधिनियम की धारा-10 में वर्णित है, का अभी तक गठन नहीं किया गया है।

(ii) रोकड़ तथा बैंक

(i) कई प्रकार की रसीद पुस्तकें मौजूद थी, कम्प्यूटर सेन्टर रसीद-पुस्तकें तथा ख्वाजा मॉडल स्कूल रसीद पुस्तकें क्रमशः उनके स्वयं के द्वारा ही छपवा ली गई थी। सभी रसीद पुस्तकों की मॉनीटरिंग के लिए केवल एक ही प्रकार की रसीद पुस्तकें ही छपवाई जानी चाहिए।

(ii) उपर्युक्त रसीद-पुस्तकें स्टोर कीपर के बजाए रोकड़िए के कब्जे में है।

(iii) अप्रयुक्त रसीद पुस्तकों की भौतिक रूप से जांच नहीं की गई थी।

(iii) क्रय एवं विक्रय

(i) क्रय केन्द्रीयकृत नहीं है।

(ii) सामग्री/आपूर्ति केन्द्रीय स्टोर की बजाए विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त की जा रही है।

(iii) क्रय आदेश रजिस्टर, जिसमें प्रत्येक क्रय का प्रारम्भ से अन्त तक ब्यौरे रखे जाते हैं, संधारित नहीं किया गया है।

(iv) स्थाई परिसम्पत्तियां

(i) सम्पत्ति रजिस्टर को अद्यतन नहीं किया गया था। रजिस्टर में चल आस्तियों को शामिल नहीं किया गया था। रजिस्टर के अंकों का लेखाओं से मिलान नहीं किया गया है।

(ii) इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी कि सभी सम्पत्तियां उनके कब्जे में हैं तथा कोई अतिक्रमण मौजूद नहीं है।

(iii) प्रत्यक्ष-सत्यापन के लिए कोई लिखित क्रियाविधि नहीं है।

(iv) भवनों को आग, दंगे तथा सिविल उपद्रव इत्यादि के विरुद्ध बीमित नहीं कराया गया है।

v. स्टॉक

कच्चे माल जैसे चीनी, चावल, गेहूं, चन्दन इत्यादि का न्यूनतम एवं अधिकतम स्टॉक-स्तर तब तक बनाए रखने के लिए स्टॉक के स्तर हेतु कोई मानक मौजूद नहीं है।

एस. के. भार्गव

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.सी. III

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2008-09

दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर ।

यह मेरा सोभाग्य है के मैं दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के प्रशासन पर अपने कार्यकाल की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2008-09 प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

दरगाह प्रशासन ने प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी कार्य किया । इन कार्यों की रिपोर्ट को आगे के पृष्ठों पर अंकन किया गया है ।

I. प्रबंधन

भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन संख्या: एस.ओ.1456(ई) दिनांक 24.08.2007 के द्वारा निम्न व्यक्तियों को दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर का सदस्य नियुक्त किया, जिन्होंने कमेटी की तरफ से जायरीन की सेवार्थ अपनी समर्पित सेवाये जारी रखी ।

- | | | |
|-------|------------------------------------|-------------|
| i. | जनाब नवाब मोहम्मद अब्दुल अली साहब, | चेन्नई । |
| ii. | जनाब हाजी हाफिज वकील अहमद साहब, | सुलतानपुर । |
| iii. | जनाब मोहम्मद इलियास कादरी साहब | अजमेर। |
| iv. | जनाब प्रोफेसर (डॉ) इब्राहीम साहब, | दिल्ली । |
| v. | जनाब प्रोफेसर सोहेल अहमद खान साहब, | पटना । |
| vi. | जनाब ए.एच. खान चोधरी साहब, | दिल्ली । |
| vii. | जनाब एम.एस.एम तिरमीजी, | अहमदाबाद । |
| viii. | जनाब बदरुद्दीन जी शेख साहब, | अहमदाबाद । |
| ix. | जनाब घोले इस्माईल मुअल्लिम साहब, | रायगढ़ । |

II. दरगाह कमेटी अजमेर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण ।

1. मजार मुबारक पर रोजाना फूल, संदल एवं मोमबत्तियाँ पेश करना ।
2. माह शव्वाल में हजरत ख्वाजा उस्मान हारुनी (र.अ.) के उर्स का इंतजाम ।
3. अंदरून दरगाह शरीफ में मुहर्रम शरीफ का इंतजाम और चिल्ला हजरत बाबा फरीद (र.अ.) को खुलवाना ।
4. खुल्फा-ए-राशेदीन और बुजुर्गाने दीन की फातिहा कराना ।
5. माहे रमजान में प्रतिदिन खास लंगर के जरिये सहर ओर अफतार का प्रबंध ।
6. दीनी तालीम के लिये दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का संचालन ।
7. सी.बी.एस.ई., द्वारा मान्यता प्राप्त ख्वाजा माडल स्कूल का संचालन (अग्रेजी माध्यम की स्कूल) जिसमे धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है ।
8. गरीब नवाज कम्प्यूटर सेन्टर का प्रबंधन ।
9. बेवाओं ओर जरूरतमंदों को वजीफा ।

10. तीन अलग अलग दवाखानों, यूनानी, होम्योपैथिक एवं ऐलोपैथिक दवाखानों का संचालन । निःशुल्क मेडीकल सलाह के अतिरिक्त निःशुल्क दवाईयों का भी वितरण ।
11. मेडीकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी छात्रों को कोर्सेस के लिये छात्रवृत्ति ।
12. ईदगाह का प्रबंधन एवं अन्य मस्जिदों को वित्तीय सहायता ।
13. लावारिस मय्यतो का निःशुल्क कफन दफन ।
14. दरगाह में स्वच्छ ट्रिपल फिल्टर्ड पीने के पानी का इंतजाम ।
15. वजू के लिये साफ पानी का इंतजाम । सर्दी के मौसम में तीन मर्तबा गर्म पानी की सप्लाई ।
16. उर्स एवं अन्य धार्मिक उत्सवों के दौरान शामियानों का इंतजाम ताकि जायरीन को धूप, गर्मी, बारिश एवं सर्दी से बचाया जा सके ।
17. मोरुसी अमले को तनख्वाह (हकूक) की अदायेगी ।
18. राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम ।
19. सोसायटी के कमजोर तबके के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन ।
20. राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्व विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन एवं मुलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना ।
21. सुरक्षा हेतु एकसरे बैगेज स्केनिंग मशीन एवं सी.सी.टी.वी. केमरे उपलब्ध कराना ।

III. वर्ष 2008-2009 के दौरान किये गये प्रोजेक्ट्स / कार्य ।

दरगाह कमेटी का मुख्य उद्देश्य “जायरीन की सेवा” मुलभूत विकास के जरिये एवं सूफी संत ख्वाजा मोईनुददीन चिश्ती (र.अ.) की शिक्षाओं का विस्तार करना है । इस ध्येय को पाने के लिये यह आवश्यक है कि निरंतर हर तरफ प्रयास जारी रहें । दरगाह कमेटी ने निम्न प्रोजेक्ट्स को वर्ष 2008-2009 दौरान क्रियान्वित किया है ।

1. दरगाह जायदाद, लेखों, दान एवं अतिथिगृह के रिकार्ड्स का कम्प्यूटीकरण किया गया है ।
2. देश के विभिन्न भागों में दरगाह कमेटी की जायदादों की तलाश, उनको चिन्हित करना, राजस्व विभाग से संबंध स्थापित करना, कानूनी कार्यवाही एवं कमेटी के अथक प्रयासों से लाखों रुपये मूल्य की जायदाद दरगाह कमेटी ने अपने कब्जे में ली है ।
3. अनाधिकृत कब्जेधारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही एवं मुहिम चलाना । लाखों रुपये मूल्य की जायदादों का कब्जा लेना ।
4. जायरीन को सुविधायें देने हेतु अजमेर में दरगाह कमेटी की पाँच बड़ी जायदादों के विकास हेतु जायदादों का सर्वे, नक्शे एवं तख्तीना बनवाना ।
5. झालरा का पुनःउद्धार जिसको कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की श्रेणी में लिया ।
6. दरगाह कमेटी के हितार्थ 100 से अधिक किरायादारों पर कानूनी कार्यवाही ।

7. दरगाह कमेटी के नज़र दफतर का जीर्णोद्धार ।
8. संदल खाना मस्जिद का जीर्णोद्धार ।
9. समय समय पर गरीब नवाज़ गेस्ट हाउस का पुनःउद्धार ।
10. विद्युत सप्लाई बन्द होने पर आधुनिक जेनेरेटर्स द्वारा निर्बाध विद्युत सप्लाई की व्यवस्था ।
11. विश्रामस्थली कि 230 बीघा क्षेत्र में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया । इसी प्रकार भूमिगत वाटर टैंक का कार्य भी पूर्ण हो चुका है । प्रथम ब्लॉक, 28 डोरमीट्रीज के निर्माण हेतु निविदाओं को मंजूरी दी जा चुकी है ।
12. दरगाह कमेटी की गुजारिश पर श्रीमती हमीदा आबदी, सलाहकार, एंव उनकी टीम, तकनीक और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार की अगुवाई में मजार शरीफ से उतरे हुये फूलों के इस्तेमाल बाबत प्रोजेक्ट के लिये दरगाह कार्यालय अजमेर का दौरा किया । यह बात सर्वविदित है कि वर्तमान समय में मजार शरीफ से उतरे हुये फूलों को एक कुएँ में डाल दिया जाता है जिस पर दरगाह कमेटी का लगभग 1.5 लाख रुपये वार्षिक खर्च होता है । इस उद्देश्य / ध्येय के साथ कि मजार शरीफ से उतरे हुये फूलों को अहताराम, अदब के साथ प्रयोग में लिया जा सके, इसके लिये टीम ने सर्वे किया और प्राजेक्ट की तकनीकी को कार्य करने योग्य माना । प्राजेक्ट के मुख्य बिन्दू निम्न है :-
 - कुएँ में इकट्ठा किये जाने वाले गुलाब के फूलों से अर्क गुलाब निकाला जायेगा ।
 - इसी तरह अर्क गुलाब निकालने के बाद उत्सर्जित पदार्थ से अगरबत्ती बनाई जायेगी ।
 - उपरोक्त दो उत्पाद बनाने के बाद बचे हुये पदार्थ की खाद बनाई जायेगी ।
 - लगभग 30 से 40 व्यक्तियों को इससे रोजगार मिलेगा ।
 - उपरोक्त उत्पादों के विपणन के बाद दरगाह कमेटी को अतिरिक्त आय होगी ।

IV. उर्स एंव उत्सवों का प्रबंधन ।

796 वाँ उर्स जुलाई 2008 में सम्पन्न हुआ जिसमें 5 लाख जायरीन ने गुम्बद मुबारक की जियारत की । उर्स दुर्घटना रहित रहा जिसमें जायरीन को मुलभूत सुविधाये दरगाह कमेटी की जानिब से दी गई । इन व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय एंव अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया । कई हस्तियों ने अपनी अकीदत का नजराना पेश किया ओर उर्स में अच्छे इंतैजामात को सराहा ।

दरगाह कमेटी ने मिनी उर्स (मुहर्रम) के भी प्रबंध किये । दरगाह कमेटी जिला प्रशासन अजमेर, पुलिस विभाग, नगर परिषद, गुप्तचर विभाग एंव अन्य विभागों का धन्यवाद देती है जिसके फलस्वरूप उर्स भलीभाँति सम्पन्न हुआ ।

V. प्रशासन:

1. सोहार्दपूर्ण वातावरण बनाया गया जिसके लिये दरगाह कमेटी ने विभिन्न संस्थाओं जैसे सज्जादानशीन, खुद्दाम एंव जायरीन में आपसी सामंजस्य बनाया ।

वर्ष के दौरान उपरोक्त संस्थाओं से सामांजस्य कायम रखा गया ताकि किसी भी कारण कोई विवाद न होने पाये। कमेटी ने सबको सम्मान दिया। दरगाह कमेटी ने एक्ट और बायलॉज के विभिन्न Provisions के तहत कार्य किया दरगाह शरीफ की प्रबंध व व्यवस्था की।

2. वेबसाईट को समय समय पर अपडेट करना ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं कमेटी की साफ छवि जनता में बने। दरगाह कमेटी के सही स्तर का संदेश बुकलेट द्वारा जनता एवं जायरीन में पहुँचा। बुकलेट के द्वारा ही दान की आय में वृद्धि हुई।
3. कम्प्यूटीकरण, उच्चस्तरीय प्रोफार्मा और रिकार्ड्स के सही रखरखाव के कारण दरगाह कमेटी की छवि में इजाफा हुआ।
4. जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं राज्य सरकार से उत्तम तालमेल के कारण दरगाह कमेटी राज्य के नक्शे में उभर कर सामने आई। माननीय न्यायालयों के फैसलों को लागू कराने में जिला प्रशासन एवं पुलिस ने सहयोग दिया।

VI. ख्वाजा मॉडल सैकण्डरी स्कूल, अजमेर।

ख्वाजा मॉडल सैकण्डरी स्कूल का सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली द्वारा मान्यता दिये जाने के बाद कमेटी ने तीव्रता से दोगुने जोश के साथ कार्य किया एवं परिणामस्वरूप छात्रों की संख्या एक वर्ष में 316 से बढ़कर 425 हो गई। अतिरिक्त कक्षाएँ लगाने के कारण अकादमिक स्तर बढ़ा। प्रत्येक छात्र के कार्य पर ध्यान एवं मध्यम दर्जे के छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाएँ लगाने के कारण उनमें सुधार आया। छात्रों के लिये English Spoken Classes लगाई ताकि उनकी झिझक निकल जाये। विद्यालय में नैतिक मूल्यों के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। तृतीय भाषा के रूप में उर्दू भी पढ़ाई जाती है। संस्कृत भी अप्रैल 2009 से लागू की जायेगी। शिक्षकों के प्रयासों से स्कूल का नतीजा अच्छा रहा और 90 % छात्रों ने अच्छी श्रेणी पाई।

स्कूल प्रशासन ने सांस्कृतिक और Co-Curricular गतिविधियों द्वारा छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्य का विकास किया। इस उद्देश्य को पाने के लिये कक्षा एवं आयु के अनुरूप छात्रों का चुनाव किया गया। वाद विवाद, स्पर्धा, भाषण, ग्रुप वार्तालाप, खेल एवं गानों के द्वारा छात्रों की योग्यता को तराशा गया।

विद्यालय बहुत ही तीव्र गति से राज्य की मुख्य धारा में मिल चुका है एवं राजस्थान सरकार ने ख्वाजा मॉडल स्कूल को आर.ए.एस., एवं राजस्व विभाग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये चिन्हित किया है।

छात्रों के ज्ञान वृद्धि के लिये शैक्षिक भ्रमण किये एवं प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिये पिकनिक पार्टी की व्यवस्था की गई।

विद्यालय में खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिसके लिये वार्षिक एथलेटिक मीट का आयोजन दिसम्बर 2008 में किया गया।

कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये शिक्षा का प्रावधान कमेटी के एजेण्डे में सर्वोपरि है एवं कमेटी इसको लागू कर रही है ।

जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं का प्रश्न है, कमेटी ने विद्यालय के भवन का विस्तार किया है । विद्यालय के प्रथम तल के 12 कमरों का निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है । दरगाह अपार्टमेंट्स को छात्रावास के रूप में चिन्हित किया जा चुका है । विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं आधुनिक कैंटीन भी प्लान में शामिल किये गये हैं ।

VII. दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया :

दरगाह कमेटी की सफलता के साथ दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का (जो कि एक धार्मिक स्कूल है, ख्वाजा गरीब नवाज (र.अ.) की शिक्षाओं का प्रचार कर रही है) संचालन कर रही है । दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया में उच्चस्तरीय पाँच आलिम, फाजिल, कामिल, हाफिज, कारी एवं लाइब्रेरियन हैं इस समय दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया में 77 छात्र कक्षा ऐदादिया, ऊला, सानिया, राबिया, तेहतानिया ओर हिफज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । कमेटी ने 65 छात्रों के लिये भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था की है । इस और प्रयास जारी है कि दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का अलग से भवन हो जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएँ छात्रों को उपलब्ध रहें ।

VIII. वित्त:

निम्नलिखित सारणी दरगाह समिति की आय एवं खर्च की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करती है ।

<u>दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर ।</u>			
<u>बजट प्रस्ताव</u>			
मुख्य हेड	आय रुपयों (लाख में)		
	2008-09		2009-10
	Actual	Budgeted	Budgeted
जागीर	2.75	3.06	2.78
जायदादों से किराया	41.69	41.35	40.25
दान एवं नज़ूर	154.89	147.80	164.35
आरामगाह	107.61	102.00	122.00
विकास कार्यों के लिये दान	00.00	11.00	00.00
शिक्षा	16.63	16.00	22.50
विविध	20.68	16.60	23.30
योग	344.25	337.81	375.18

दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर ।

बजट प्रावधान

खर्च :

मुख्य हेड ए. राजस्व खर्च	आय रुपये (लाख में)		
	2008-2009		2009-2010
	Actuals	Budgeted	Budgeted
वेतन एवं भत्ते	103.29	104.02	136.48
कार्यालय के खर्च	19.15	21.80	22.00
दरगाह शरीफ के खर्च	*96.79	70.45	78.35
मजार शरीफ के खर्च	8.24	7.76	9.79
चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च	1.48	2.20	1.95
दारुल उलूम खर्च	3.87	4.00	4.15
ख्वाजा मॉडल स्कूल के खर्च	11.28	28.95	12.10
कम्प्यूटर सेन्टर के खर्च	3.81	2.90	5.40
छात्रवृत्ति पर खर्च	2.77	3.00	3.50
कल्याणकारी एवं अन्य खर्च	11.24	17.44	18.40
आरामगाह के खर्च	25.76	25.85	27.00
दरगाह अपार्टमेंट के खर्च	1.29	2.50	2.30
मरम्मत एवं नवीनीकरण	1.63	1.00	2.00
विविध खर्च	2.55	2.20	2.20
स्कूल भवन का निर्माण	15.57	15.00	40.00
कुल योग	308.72	309.07	365.62

*सुरक्षा पर हुआ खर्च भी इसमें सम्मिलित है ।

मुख्य हेड	आय रुपये (लाख में)		
	2008-2009		2009-2010
	Actuals	Budgeted	Budgeted
1. विकास के कार्य (केपिटल खर्च)			
2. स्कूल बिल्डिंग की नाले से बचाव हेतु दीवार का निर्माण	*1.83		--
3. शौचालयों का निर्माण	1.09		5.0
4. अजमेर शहर में विविध जायदादों का विकास	0.80		
5. नजूर कार्यालय का नवीनीकरण ।	2.12		
6. दान प्राप्त / खर्च किया गया	16.04		
6. स्कूल बस	10.52		
उप-योग	32.40		
टोटल (बी)	32.40	00.00	5.00
टोटल (ए)	308.72	309.07	365.62
	341.12	309.07	370.62

* इस कार्य के द्वारा 50 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति प्राप्त हुई ।

IX. दरगाह कमेटी की बैठके :

वर्ष के दौरान दरगाह कमेटी की पाँच बैठकें दरगाह के मामलात के संबध में आयोजित हुई ।

X. वी.वी.आई.पी. एवं वी.आई.पी. का आगमन :-

निम्नलिखित अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने दरगाह शरीफ की जियारत की जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है ।

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. श्री एस.के.सिंह साहब, | महामहिम राज्यपाल राजस्थान । |
| 2. श्री अशोक गहलोत जी, | मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार । |
| 3. श्री लालजान बाशा साहब, | अध्यक्ष, संयुक्त संसदीय समिति । |
| 4. श्री सुजीत दत्ता जी, | सांसद एवं संयुक्त सचिव, भारत सरकार । |
| 5. श्री मेहमूद अख्तर साहब, | उप सचिव, भारत सरकार । |
| 6. श्री लालू प्रसाद यादव, | रेल मंत्री, भारत सरकार । |
| 7. श्रीमती सलमा अन्सारी साहिबा, | धर्म पत्नी श्री हामिद अन्सारी साहब, उप-राष्ट्रपति, भारत गणराज्य । |
| 8. श्री सेलजा, | माननीय राज्य मंत्री, भारत सरकार । |
| 9. श्रीमती पनबाका लक्ष्मी, | माननीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार । |

XI. लेखों का अंकेक्षण

दरगाह के लेखों एवं रिकार्डस का अंकेक्षण बराये साल 2007-08 प्रिंसिपल अकाउण्टेन्ट जनरल, राजस्थान जयपुर की टीम ने किया । ऑडिट 27 जनवरी 2009 से 11 फरवरी 2009 तक किया गया । कुछ सुझाव जो के सामान्य प्रकृति के थे आडिट ने दिये जिसकी पालना से कार्य में और बेहतरी आयेगी ।

XII. धन्यवाद

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तमाम दरगाह कमेटी के सदस्यों का मैं आभारी हूँ जिनके दिये गये मार्गदर्शन से दरगाह शरीफ का प्रबंधन सुचारु रूप से हो पाया । दरगाह कमेटी के सहयोग के परिणाम स्वरूप प्रति दिन एवं उर्स एवं मुख्य दरगाह शरीफ की रसूमात का प्रबंधन बिना किसी व्यवधान के हुआ ।

मैं अपने कर्तव्यों में असफल रहता यदि मुझे अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन अजमेर, पुलिस विभाग, नगर परिषद, विद्युत विभाग एवं अन्य

विभागों से निरन्तर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता । इनके सहयोग से दरगाह प्रशासन में गुणवत्ता आई ।

मैं यहाँ अपनी रिपोर्ट इस नोट के साथ समाप्त करता हूँ कि आने वाला वर्ष भी चुनौतीपूर्ण होगा ।

अहमद रज़ा
नाजिम एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब,
अजमेर

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

हमने 31 मार्च 2009 तक दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के संलग्न तुलन-पत्र और दरगाह ख्वाजा साहब, अधिनियम 1955 की धारा 19 (i) के साथ पठित नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) को अन्तर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा कर ली है। लेखापरीक्षा वर्ष 2003-04 से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों में दरगाह ख्वाजा साहब, के समस्त युनिटों के लेखे शामिल हैं । इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व दरगाह ख्वाजा साहब के प्रबन्धन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के सम्बन्ध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के सम्बन्ध में वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है ।

3. हम ने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं । लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना, रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों

में प्रकटन शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार मुहैया करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

- i- हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक थे,
- ii- इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत के महानियंत्रक लेखा द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं।
- iii- हमारी राय में दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए लेखाओं की समुचित बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख, जहां तक ऐसी बहियों के सम्बन्ध में हमारी जांच से प्रकट होता है, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 की धारा-20(2)(डी) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

iv- हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :-

लेखों पर टिप्पणियां

क- तुलन -पत्र

क.1 दायित्वरू. 6.96 करोड़

₹ 1.07 लाख का प्रावधान (₹ 1.00 लाख 11.10.2007 को घटित दुर्घटना में मृत/चोट ग्रस्त व्यक्ति के परिवारों को अनुग्रह पूर्वक भुगतान एवं वर्ष 2003 के डीजल एवं पेट्रोल के बकाया बिल के भुगतान के ₹ 6926) रखा गया था। चूंकि अब तक मृत परिवारों का पता ठिकाना ज्ञात नहीं हो सका। अतः दरगाह समिति द्वारा अनुग्रह पूर्वक एवं डीजल एवं पेट्रोल के बिल भुगतान को नहीं करने का निर्णय लिया गया, किंतु प्रावधान के समायोजन की कार्रवाई नहीं की गई। यह चालू दायित्वों के अधिक बताए जाने एवं आय के ₹ 1.07 लाख से कम बताए जाने में परिणामित हुआ।

दरगाह ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि गलती के परिशोधन हेतु आवश्यक विपरीत प्रविष्टि करदी जाएगी।

क-2 आस्तियां ₹ 6.96 करोड़

क.2.1 स्थायी आस्तियां ₹ 4.53 करोड़

(i) यह ₹ 16.34 लाख से अधिक बताया गया जैसा कि ख्वाजा मॉडल स्कूल अब तक पूर्ण नहीं हुआ है, इस प्रकार प्रगति में कार्य को इस सीमा तक कम बताया गया।

दरगाह ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।

(ii) यह ₹ 1.27 लाख से कम बताया गया, जैसा कि विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त सॉफ्टवेयर को व्यय के रूप में बताया गया है। यह इस सीमा तक अधिशेष को कम बताए जाने में भी परिणामित हुआ।

दरगाह ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।

ख- आय एवं व्यय लेखा

ख.1 व्यय ₹ 3.28 करोड़

आस्तियां पक्ष में राशि ₹ 6.67 लाख अप लिखित किए गए एवं इसका प्रभाव आय एवं व्यय लेखा की बजाय पूंजीगत निधि में बताया गया। परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि को कम बताया गया एवं इस सीमा तक अधिशेष को अधिक बताया गया।

दरगाह ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि जो आस्तियां अप्रचलित हो गईं उन्हें अपलिखित किया जाएगा व इस हानि को आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया जाएगा।

ग- सामान्य

वर्ष 2007-08 में चिन्हित विन्यास निधि ₹ 9.50 लाख (प्राप्त दान ₹ 8.50 लाख अतिथि गृह भवन निर्माण एवं विद्यालय निर्माण हेतु एवं ₹ 1.00 लाख चंदन लकड़ी के) बनाई गई थी इसे वर्ष 2008-09 के दौरान पूंजीगत निधि में शामिल किया गया था, क्योंकि दान विशिष्ट उद्देश्य हेतु हुआ था इसलिए यह “चिन्हित विन्यास निधि” पृथक शीर्ष से दर्शाया जाना था।

दरगाह ने बताया कि ₹ 9.50 लाख की पूंजीगत निधि लेखापरीक्षा टिप्पणी की अनुपालना में बनाई गई थी। अनुवर्तित वर्ष में यह निधि स्थायी जमा रसीदों में विनिहित कर दी गई।

दरगाह का यह लेखाकरण व्यवहार सही नहीं है। यह निधि पृथक रूप से “चिन्हित विन्यास निधि” एवं स्थायी जमा रसीदों को चिन्हित विन्यास निधि विनिधान के रूप में दर्शाया जाना चाहिये।

लेखाओं पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव:-

पिछले पैराओं में दी गई टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह हुआ है कि 31 मार्च 2009 को आस्तियों ₹ 1.27 लाख से कम बताई गई, दायित्व ₹ 5.60 लाख से कम बताए गए एवं अधिशेष ₹ 4.33 लाख से अधिक बताए गए ।

प्रबन्धन-पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल न की गई कमियां उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबन्धन पत्र के माध्य से प्रबन्धन की सूचना में लाई गई है ।

v- पिछले पैराग्राफो में हमारी अभ्युक्तियों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा-बहियों के अनुरूप हैं ।

vi- हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबन्ध-1 में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं :-

- क. जहाँ तक यह 31 मार्च 2009 को दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के कार्यों के तुलन-पत्र से सम्बन्धित है ।
- ख. जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं लेखा से सम्बन्धित है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए

स्थान - जयपुर

दिनांक -29.10.2010

ह/-

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा)

राजस्थान, जयपुर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए अनुबन्ध-1

1. आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

दरगाह में प्रचलित आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है । चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा केवल अंतिम लेखे तैयार किए गए ।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

दरगाह में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का लेखापरीक्षा के दौरान मूल्यांकन किया गया, निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई ।

सामान्य-

- (i) नकद, स्टॉक एवं मूल्यावान मदों, सम्बन्धी कर्मचारियों के कर्तव्यों में क्रमावर्तन की कोई योजना नहीं है।
- (ii) दरगाह में खादियों को कार्यों के नियमन हेतु अनुज्ञप्ति दिए जाने व तैयार किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।
- (iii) वहां जायरीनों द्वारा हण्डों (देगो) में डाले जाने वाले धन पर कोई नियंत्रण नहीं है ।
- (iv) दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत वर्णित सलाहकारी समिति का अब तक गठन नहीं हुआ है।

II- नकद एवं बैंक

- (i) वहाँ कई प्रकार की रसीद पुस्तकें जैसे सामान्य रसीद पुस्तक, कम्प्यूटर केंद्र रसीद पुस्तक, एवं ख्वाजा मॉडल स्कूल रसीद पुस्तक है । ये उन्हीं के द्वारा तैयार की जाती है, रसीद पुस्तकों के प्रयोग पर कोई नियंत्रण नहीं है । सब प्रकार की रसीदों के अनुश्रवण हेतु एक ही प्रकार की रसीद बुक छपवाई जानी चाहिये ।
- (ii) अप्रयुक्त रसीद पुस्तकें भण्डार रक्षक के स्थान पर रोकड़िए के अधिकार में है ।
- (iii) अप्रयुक्त रसीद पुस्तकों की भौतिक जाँच नहीं की गई थी ।

III कय एवं विकय

- (i) कय केंद्रीकृत नही थें।
- (ii) सामग्री आपूर्ति केन्द्रीय भण्डार के स्थान पर विभिन्न विभागों से प्राप्त की जा रही थी ।
- (iii) सभी विवरणोंयुक्त मदवार कय पंजिका का संधारण नही किया जा रहा था ।

IV स्थायी आस्तियां

- (i) सम्पत्ति पंजिका अध्यतित नही की गई, इस पंजिका में चल आस्तियों को सम्मिलित नही किया गया । पंजिका के अंको का लेखों से मिलान नही किया गया है।
- (ii) वहाँ इस प्रकार के प्रमाणन कि "समस्त समस्त सम्पत्ति उनके कब्जे में है एवं उस पर कोई अतिक्रमण नही है" कोई व्यवस्था नही है ।
- (iii) वहाँ दरगाह समिति द्वारा दान में प्राप्त स्वर्ण एवं चांदी के आभूषणों के मूल्य के मूल्यांकन का कोई मानक तंत्र नही है।
- (iv) वहां आस्तियों के भौतिक सत्यापन का कोई तंत्र नही है ।
- (v) अग्नि, दंगों एवम् नागरिक उत्पात के सम्बन्ध में भवनों का बीमा नही किया गया है ।

सहा.महालेखाकार/आई.सी.आ

National Housing Bank

New Delhi, the 24th December 2010

No. NHB.HFC.DIR.2/CMD/2010

In exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system to the advantage of the country, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010(hereinafter referred to as the principal Directions), shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely:

1. In the principal Directions after paragraph 27, the following paragraph shall be inserted, namely :

“ 27A. Loan to Value (LTV) Ratio

No housing finance company shall (i) grant housing loans upto Rs. 20 lakh to individuals with LTV ratio exceeding 90% and (ii) grant all other housing loans above Rs. 20 lakh to individuals with LTV ratio exceeding 80%.”

2. In sub-paragraph (1) of paragraph 28 of the principal Directions, for clause (iv), the following shall be substituted, namely:

“iv Standard Assets

(a)	Standard Assets in respect of all loans other than housing loans to individuals (which will include loans to builder/corporates/agencies for housing and other purposes, loan against property etc.)	A general provision of 0.4% of the total outstanding loans other than housing loans to individuals to be made as under : i) 0.2% by March 31, 2011 ii) 0.4% by September 31, 2011
(b)	Standard Assets in respect of housing loans at teaser/special rates i.e. housing loans at comparatively lower rates of interest in the first few years after which rates are re-set at higher rates	2% provision on the total outstanding amount of such loans. The provisioning of these loans to be re-set after one year at the applicable rates from the date on which the rates are re-set at higher rates if the accounts remain ‘standard’.

(c)	Standard Assets in respect of loans given for the purpose of insurance of property/borrower in case of individual housing loans.	NIL
-----	--	-----

3. In sub-paragraph (3)(2) of paragraph 30 of the principal Directions, for clauses (b)(ii) and (b)(iii), the followings shall be inserted, namely:

(b)(ii)	Housing loans sanctioned to individuals above Rs. 30 lakh but below Rs. 75 lakh secured by mortgage of immoveable property which are classified as standard assets with LTV ratio is = or < 75%	75%
(b)(iii)	Housing loans sanctioned to individuals upto Rs. 75 lakh secured by mortgage of immoveable property which are classified as standard assets with LTV ratio is > 75%	100%
(b)(iv)	Housing loans of Rs. 75 lakh and above, sanctioned to individuals irrespective of LTV ratio, secured by mortgage of immoveable property, which are classified as standard assets	125%
(b)(v)	Loans given for the purpose of insurance of the property /borrower in case of individual housing loans	Same as applicable to the respective housing loan.

4. In Schedule II, in Part D

For item description, item code and risk weight given in III (f)(iii) & (iv), the following shall be substituted, namely:-

(iii)	Housing loans sanctioned to individuals above Rs. 30 lakh but below Rs. 75 lakh secured by mortgage of immoveable property which are classified as standard assets with LTV ratio is = or < 75%	237(iii)		75	
(iv)	Housing loans sanctioned to individuals above Rs. 30 lakh but below Rs. 75 lakh secured by mortgage of immoveable property which are classified as standard assets with LTV ratio is = or > 75%	237(iv)		100	

(v)	Housing loans of Rs. 75 lakh and above, sanctioned to individuals irrespective of LTV ratio, secured by mortgage of immoveable property, which are classified as standard assets	237(v)		125	
(vi)	Loans given for the purpose of insurance of the property /borrower in case of individual housing loans	237(vi)		Same as applicable to the respective housing loan	

R. V. VERMA
Chairman & Managing Director

CORPORATION BANK

Manglore, the

In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the name of the Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Name of the Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Name of the Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force with effect from the 2nd day of June 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations.
2. In the Name of the Banks (Officers') Service Regulations, 1979, (hereinafter referred as the said regulations), in regulations 3, —
 - (i) For clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—
(g) "Family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent unmarried children (including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer;
 - (ii) For clause (o), the following clause shall be substituted, namely :—
(o) "Wholly dependent children or parents" mean children or parents having an income not exceeding Rs. 2,550 per month.

Note :— If the income of one of the parents exceeds Rs. 2,550 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 2,550 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employee;

3. In the said regulations, in regulation 4, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

'(4) On and from the 1st day of November 2002, the scales of pay specified against each grade shall be as under :—

(a) Top Executive Grade :

Scale VII = Rs. 29340— $\frac{680}{2}$ —30700— $\frac{900}{1}$ —31600— $\frac{1000}{1}$ —32600

Scale VI = Rs. 22620— $\frac{680}{4}$ —29340

(b) Senior Management Grade :

Scale V = Rs. 24140— $\frac{620}{4}$ —26620

Scale IV = Rs. 20480— $\frac{560}{1}$ —21040— $\frac{620}{5}$ —24140

(c) Middle Management Grade :

Scale III = Rs. 18240— $\frac{560}{5}$ —21040— $\frac{620}{2}$ —22280

Scale II = Rs. 13820— $\frac{500}{1}$ —14320— $\frac{560}{10}$ —19920

(d) Junior Management Grade :

Scale I = Rs. 10000— $\frac{470}{6}$ —12820— $\frac{500}{3}$ —14320— $\frac{560}{7}$ —18240.

Note :— Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2002 on stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise;

(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2) (3) and (4) shall be construed as requiring the bank to have at all times, officers serving in all these grades.'

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely: -

'5. Increments. - (1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely: -

- (a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government;
- (c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs.560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.620 for officers in the last stage of Scale III;

Provided that on and from the 1st day of November, 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment:

Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note: Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

- (2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers/Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation: (a) In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

(b) on and from the 1st day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below:

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed: both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year, of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs.250 per month after two years, of which Rs.200 shall rank for superannuation benefits.

(c) on and from 1st day of November, 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed: both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale; (ii) Rs.300 per month after two years on reaching top of the scale:

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal allowance in terms of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) on and from the 1st day of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale; (ii) Rs.360 per month after two years on reaching maximum of the scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

(e) on and from the 1st day of November, 2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale; (ii)Rs.750 per month after two years on reaching maximum of the Scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note : (i) if an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers/Certified Associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) on and from the 1st day of November, 1994, Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and superannuation benefits.

(iii) an officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered.

(iv) if an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.

(v) if an officer, as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s, he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.

- (3)(a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1st day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1st day of November 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note: There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

- (b) an officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st day of November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from the 1st day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of November, 1993, plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1993 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

- (c) on and from the 1st day of November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1997 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

- (d) on and from the 1st day of November 2004, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.2002 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

Note: (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (C) of the tables in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance as indicated in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of regulation 4 is earned.

(iii) on and from the 1st day of November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st day of November, 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale.

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

‘(4) On and from the 1st day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under:

(a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(b) during the period from the 1st day of November, 2002 to 31st day of January, 2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates :-

- (i) 0.18% of ‘pay’ upto Rs.9,650 plus
- (ii) 0.15% of ‘pay’ above Rs.9,650 and upto Rs.15,350 plus
- (iii) 0.09% of ‘pay’ above 15,350 and upto Rs.16,350 plus
- (iv) 0.04% of ‘pay’ above Rs.16,350

- (c) on and from the 1st day of February, 2005, dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note: (A) "Pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d) and (e) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.'

6. In the said regulation, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely:-

'22. House Rent Allowance – (1) (a) on and from the 1st day of November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major 'A' class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'.	9% of the pay per month.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	8% of the pay per month.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above	7% of the pay per month.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of

pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table, whichever is lower.

- (2)(a) On and from the 1st day of November, 2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely: -

TABLE

	Where the place of work is in	House Rent Allowance payable shall be
	(1)	(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him/her shall be the actual rent paid by him/her for the residential accommodation in excess over 1.75% of Pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

- (3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of (A) or (B) below:-

(A)

The aggregate of: -

- (i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and
- (ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

(B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation:

- (1) For the purpose of this regulation “standard rent” means: -
 - (a) in the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government:
 - (b) where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure specified in (A) above, whichever is lower.
- (2) “Pay” for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.
- (3) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1st day of November, 1994.
- (4) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) of this regulation and regulation 23, Area I and Area II shall mean as under: -
 - Area I - Places with a population of more than 12 lakhs
 - Area II - All places not included in Area - I.

7. In the said regulations, for regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely: -

‘23. Other Allowances:

- (1) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below, namely,

TABLE

Places	Rates
(1)	(2)
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.540 per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.375 per month.
(c) Other places	Nil

- (2) On and from the 1st day of November, 2002, the rates of special area allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1st day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210 per month or Rs.185 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
- (4) On and from the 1st day of January, 2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance at the rate of Rs.500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children studying:

Provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1st day of June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1500 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month.

- (6) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

- (7) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1st of April and 30th September, a closing allowance of Rs.250 for each of the two closings.

- (8) On and from the 1st day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.125 per month
- (9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.
- (10) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1150 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.500 per month
(iii) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.400 per month.

Note : (a) officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn:

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted, namely:-

‘24. Medical Aid:-

- (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely:-

- (a) Medical Expenses:- On and from the 1st day of February, 2004 an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.3750 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.5000 or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months, i.e. from February 2004 to December 2004.

Explanation: - “Family” of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3.

- (b)(i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization.

- (ii) on and from the 1st day of May, 2005, reimbursement of hospitalisation expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated the 2nd day of June, 2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.600 per day.</p> <p>Family – Rs.450 per day.</p> <p>(ii) Other charges –</p> <p>At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.800 per day.</p> <p>Family – Rs.600 per day.</p> <p>(ii) Other charges –</p> <p>At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>

- (2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalization etc.) specified in sub-regulation (1) above. and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalization, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalization, etc.)

(3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.'

9. In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-

'25. Residential Accommodation.- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:.

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.'

10. In the said regulations, in regulation 41, - for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

'(1) On and from the 2nd day of June, 2005, an officer shall be eligible for the following while traveling on duty, namely:-

- (i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

- (ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms. or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.
- (iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class).
- (iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km. and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.
- (v) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

(b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

- (a) Halting Allowance- On and from the 1st day of June, 2005 an officer shall be entitled to 'per diem Halting Allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
1	2		
Officers in Scale IV and above	Rs. 600	Rs. 550	Rs. 500
Officers in Scale I/II/III	550	500	400

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.700:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation: For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.'

11. In the said regulations, in regulation 42. for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

- (3) On and from the first day of April, 1997 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. as specified in the table below, namely.

TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.5,000
Middle Management and Junior Management	Rs.4,000

Provided that on and from the first day of May, 2005 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs.5000" and "Rs.4000", the letters, words and figures "Rs.8750" and "Rs.7000" had been respectively substituted.'

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely:-

44 Leave Travel Concession:

- (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or, alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.
- (2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto a distance of 4500 kms. (one way) for officers in JMG Scale I and MMG Scale II and III and 5500 kms (one way) for officers in SMG Scale IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.
- (3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time-to-time.
- (4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time, or, he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a

maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible.:

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.'

Schedule to Name of the Bank (Officers') Service Regulations, 1982

(See, sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
1.	Mizoram	(Rs.)	(Rs.)
	(a) Chimgtuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	1,000	1,300
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	800	1,050
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	600	750
2.	Nagaland	800	1,050
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) South Andaman (including Port Blair)	800	1,050
	(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	1,000	1,300
4.	Sikkim	1,000	1,300
5.	Lakshadweep Islands	1,000	1,300
6.	Assam	160	200
7.	Meghalaya	160	200

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	800	1,050
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	600	750
9.	Manipur	600	750
10	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	1,000	1,300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas.	800	1,050
11.	Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District	1,000	1,300
	(a) Niabat Bani		
	(b) Lohi		
	(c) Malhar		
	(d) Macchodi		
	(2) (a) Udampur District	1,000	1,300
	i. Dudu Basantgarh		
	ii. Lander Bhamag Illaqa		
	iii. Thakrakote		
	iv. Nagote		
	(b) All areas in Mohre Tehsil other than those included in 2(c).	1,000	1,300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	800	1,050

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(3) Doda District Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	1,000	1,300
	(4) Leh District All places in the District	1,000	1,300
	(5) Barmulla District a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa b) Matchill	1,000 800	1,300 1,050
	(6) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	600	750
	(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	600	750
	Himachal Pradesh (1) Chamba District 1(a) Pangi Tehsil 1(b) Following Panchayat and Villages of Bharmour Tehsil (i) Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah	1,000 800	1,300 1,050

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(ii) Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata		
	2. Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part 1.b above.	600	750
	3. Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).		
	(2) Kinnaur District:		
	(a) Asrang, Chitkul and HangoKuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub- Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	1,000	1,300
	(b) Entire District other than Areas included in (a) above	600	750
	(3) Kullu District:		
	3(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	1,000	1,300

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	3(b) Outer-Seraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District (excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	600	750
	(4) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti.	1,000	1,300
	(5) Shimla District : (a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	1,000	1,300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	800	1,050
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhawal and Chhota Bhawal	800	1,050
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town—Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Binwa Project, Shamnagar Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HPSEE Division, Ghuggar.	600	750
	(7) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	<p>Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gato, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.</p>		
(8)	<p>Sirmaur District:</p> <p>(a) Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil).</p> <p>(b) Thansgiri Tract</p>	600	750
(9)	<p>Solan District :</p> <p>Mangal Panchayat.</p>	600	750
(10)	<p>Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.</p>	160	200

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
13.	Uttar Pradesh: Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts: 2(a) Other area of District Pithoragarh and Uttarkashi (including District Headquarters of Uttarkashi). 2(b) Champawat District (including area of Lohaghat).	1,000	1,300
14.	Uttaranchal: Areas under Rudraprayag and Champavat Districts.	800	1,050

Notes: The principal regulations were published in the official Gazette on the ____ day of _____. The subsequent amendments were notified vide the following notifications:

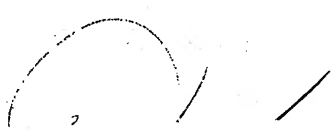
Sr. No.	Gazette Notification No.	Date
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Dargah Khwaja Saheb, Ajmer for the year ended 31 March 2007.

We have audited the attached Balance Sheet of Dargah Khwaja Saheb (DKS), Ajmer as at 31 March 2007 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Accounts for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act 1971 read with Section 19(1) of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955 . The audit has been entrusted for the period of five years with effect from 2003-04. These financial statements include the accounts of all units of the DKS. These financial statements are the responsibility of the DKS's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc, Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.



4. Based on our audit, we report that:
- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/ Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Controller General of Accounts of India.
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer as required under section 20(2) (d) of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955 in so far as it appears from our examination of such books
 - iv. We further report that :

Comments on Accounts

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities Rs. 4.68 Crore.

A.1.1 Secured loans & borrowings Rs. 25.37 lakh

This is overstated by Rs. 50,497/- as the amount of security received from contractor should be depicted under schedule "other current liabilities".

The facts have been accepted. Necessary rectifications will be done in current financial year.

A.1.2 Interest Accrued but not due on Loans / Borrowing.

Interest amounting to Rs. 60384 was paid as against the accrued interest of Rs.90793 on IInd and IVth loan borrowed on 31-3-2007. The Liability on account of balance amount of Interest accrued was not provided in the Accounts. As a result liability of Rs. 0.30 lakhs was understated and expenditure was also understated to this extent.

Dargah stated that demand was not received from Central Waqf Council therefore, not included in the creditors and it is not possible to make provisions for

actual interest. The reply is not convincing because as per accounting standard, accounts are maintained on accrual basis. If the provisions are not made correctly the accounts of the Dargah will not depict the correct picture.

A.2 Assets Rs. 4.68 Crore.

A.2.1 Fixed Assets - Rs. 3.50 Crores

- (i) This is understated by Rs. 1.68 lakh as the new nine toilets were constructed but not capitalized. As a result, the expenditure of Rs.1.68 Lakhs was overstated.

Dargah stated that expenditure was incurred on renovations work after dismantling the old toilets. The constructed value of these 9 toilets already included in the fixed assets hence treated as revenue expenditure. The reply is not tenable as the expenditure was incurred after dismantling the old toilets and thereafter new 9 toilets were constructed, which is capital expenditure.

- (ii) One time vehicle tax Rs.0.51 lakh was paid, but it was not capitalized, as a result Fixed Assets was understated and expenditure was overstated to this extent.

A.2.2 Current Assets- Loans and Advances etc. Rs. 1.18 crore.

Claims Receivable:

This is understated by Rs.0.22 lakh being the expenditure incurred on computer consumables like floppies, tonners etc. which was reimbursable from National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL) Department of Secondary and Higher Education, Government of India, New Delhi, charged as "Computer Center Expenses" in the Income and Expenditure account in place of showing the amount as receivable from NCPUL in the Balance Sheet of the Dargah. This also resulted in overstatement of Expenditure to the same extent.

Similar Comments of claims receivable of Rs. 0.31 lakh was also taken in the year 2005-06 but effect was not given in the Balance Sheet for the year 2006-07.

- A.2.3** Staff Advances Rs.3.55 lakhs shown under the head of “Income Accrued” in place of depiction of the same under head “Loans to staff & other security deposit”.

The facts have been accepted. Necessary rectification will be done in current financial year.

B Income & expenditure Account :

B.1 Expenditure Rs. 2.21. Crore :

B.1.1 Inside gumbad, Sharif expenses Rs. 5.82 lakhs.

Last Year it was pointed out that closing stock of sandal 20.45 Kg cost Rs.0.28 lakh was not shown in the Accounts. As a result expenditure was overstated and Current Assets was understated, During the current year it was observed that Sandal worth Rs. 1,74,750 (Rs. 184034- other expenses Rs. 9284.00) was purchased leaving closing stock of Sandal Rs. 25238. Thus Sandal worth Rs. 1,77,488 including closing stock for the year 2004-05 of Rs. 27976 was used in the Gumbad Sharif during the year 2006-07. Whereas the consumption was shown to Rs. 1,74,750 (excluding Rs. 9284 on account of other expenses). This resulted in understatement of expenditure to the extent of Rs. 0.03 lakh.

B.2 Income

B.2.1 Income Earned

This is understated by Rs. 2.26 lakh being room rent not received from members & Zaireen during the year 2006-07 was not accounted for. This also resulted in understatement of current assets, 'loans and advances' to the same extent.,

Dargah stated that there was no chance of recovering of Rs. 2.26 lakh from members & Zaireen so it was not accounted for .

The reply is not tenable as the amount of rent has not been written off by Dargah Committee, therefore, the amount should have been shown in current assets.

C. GENERAL

- C.1 The accounts of the Dargah were being audited by a Chartered Accountant firm in contravention of the standard terms and conditions prescribed for taking up audit under section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Power and Conditions of service) Act, 1971.

The Dargah stated that audit is conducted by C.A. as an internal auditor. The reply is not tenable as the C & AG being the sole auditor and as per terms & conditions of audit entrustment, the appointment of any primary auditor can only be made by C & AG who will conduct audit on his behalf on the basis of directions & guidelines issued by C & AG.

Similar comment was also made in the Audit Report of 2005-06.

- C.2 Depreciation has not been charged on immovable assets i.e. buildings.

The Dargah stated that it being a charitable trust its income is exempted from Income Tax. Capital & Reveue expenditure are treated as expenditure of the charitable institution. The reply is not tenable as in absence of providing depreciation, the accounts do not depict the true & fair value of immovable assets.

Similar comment was also made in the Audit Report of 2005-06.

- C.3 Rental Income and Lease Money Rs.2.46 lakhs have been written off during the year without the approval of the Dargah Committee.

The Dargah stated that the accounts for the year 2006-07 have been approved by the accounts committee. The reply is not tenable as specific approval of Dargah Committee for written off rental income and Lease Money has not been obtained.

- C.4 Donation of Rs. 8.50 lakhs for construction of guest house building in 'G-Block' and construction of school was received but the same have been shown under schedule "corpus capital fund" in place of Earmarked / Endowment fund. As the funds was received for specific earmarked purpose.

Dargah stated that earmarked/endowment fund are treated as corpus donations. The reply is not tenable. As per common format of accounts, the corpus capital fund (Schedule- 1) and Earmarked/ Endowment fund (Schedule-3) are separate and should have been shown separately in the Balance Sheet. As per comments the funds was received for specific earmarked purpose which _____ should have been shown to Earmarked/ Endowment fund in Schedule-3.

- C.5 An Investment of Rs.89,00,000/- was made with the schedule and non-schedule Bank. This have been shown in schedule-11 in Bank Balance in place of schedule-10, Investment – others.

Dargah stated that fixed deposit is the part of bank balance so this has been shown in Schedule-11 in bank balance in place of Schedule-10 , Investment others. The reply is not tenable. As per common format of accounts FDR should have been shown in Government securities schedule-10 Investment others.

C.6 **Staff contributory Fund :**

Rs. 6432393.52 was lying with Dargah Khwaja Saheb which has not been shown in the Balance Sheet in liability side as well as in Asset side under schedule-9.

Dargah stated that necessary rectification will be done in the current financial year.

- C.7 The significant accounting policy appended with the accounts as schedule-24 indicates that:-

- (i) Liability towards gratuity payable on death / retirement of employees is accrued on actuarial valuation.
- (ii) Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit at the end of each year.

On scrutiny of records, It was noticed that no such provision have been made and shown in the accounts under schedule 7 ' current liabilities and provisions'

Dargah stated that it is not possible to show the balances of gratuity and leave encashment in the balance Sheet. The reply is not tenable in view of significant accounting policy appended with the accounts as Schedule-24.

- C.8 There was no stock entry of 10 numbers of Silver bowls worth Rs.0.17 lakh received as donation for Dargah Sharif. The possession of the same was also not found with the management.

The Dargah stated that the silver bowls, are hanging in Dargah Shariff. These are not in its chest, therefore, the cost of these bowls have been booked as expenditure in the accounts for the year 2006-07. The reply is not tenable, as per accounting practices, donation received in goods/ kind may be entered in stock register to depict true and fair view of financial status.

D. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, We report that the Balance Sheet /Income & Expenditure Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters, stated above and other matters mentioned in Annexure- I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.



Dargah Shariff
Dargah Shariff

- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer as at 31 March 2007, and
- b. In so far as it relates to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

E. Effect of Audit on Accounts:

The net impact of the comments given in preceding paras is that as on 31st March 2007 assets were understated by Rs. 4.95 lakh, liabilities understated by Rs. 2.56 lakh and excess of Income over expenditure understated by Rs.2.39 lakh.

For and on behalf of the C&AG of India

Place : Jaipur

Date : 31.12.2008.

Principal Accountant General (Civil Audit)
Rajasthan, Jaipur

Annexure- I to Audit Report**1. Adequacy of Internal Audit System**

Internal audit system prevailed in the Dargah is not adequate. The said Internal auditor (Chartered Accountant) only checks and prepares final accounts only.

2. Adequacy of Internal Control System.

Internal Control System prevailed in the Dargah was evaluated during audit and the following position emerged:-

(I) General

- (i) There is no Plan of rotation of duties of employees with cash, stock and other valuables items.
- (ii) There is no system of preparing and awarding the licenses to Khadims as to regulate their functions in Dargah.
- (iii) There is no control over money dropped by Zaireen into cauldrons.
- (iv) Advisory committee as mentioned in the sections 10 of the Dargah Khwaja Saheb, Act has not been constituted till now.

(II) Cash & Bank.

- (i) There are number of types of receipts book. Computers Center receipts books and Khwaja Model School receipt books are printed respectively by themselves. In order to monitor all the receipts, one type of receipts book should be printed.
- (ii) Unused receipts books are in the possession of cashier in place of store keeper.
- (iii) Unused receipts books were not checked physically.

(III) Purchase and Sales

- (i) Purchase are not centralised.
- (ii) Material/ Supply is received by different departments in place of Central Store.
- (iii) Purchase order register having details of each purchase from beginning to end, is not maintained.

(III) Fixed Assets.

- (i) Updation of the property was not done. Moveable assets were not included in the register . Figures of register are not reconciled with accounts.
- (ii) There is no system to certify that all property are in their possession and their is no encroachment.
- (iii) There is no written procedure for physical verification .
- (iv) Buildings are not insured with respect to fire, riot and civil commotion etc.

(IV) Stock.

There is no norms for stock level of raw material viz, Sugar, Rice, Wheat, Sandal etc., to hold at minimum and maximum stock level.

S. K. BHARGAVA
Sr. Audit Officer/ IC-I

Annual Administrative Report

Of

Dargah Khwaja Sahab (R.A.), Ajmer

For The Year 2007-2008

It is my privilege and also a matter of immense pleasure to make a presentation on the Administrative aspects of Dargah Khwaja Sahab of Ajmer, for the year 2007-2008.

The year was full of events in connection with the activities of Dargah Management, Developmental Activities, community services etc. During the year there was also change of guard.

A. The Management :

The Government of India vide Gazette Notification No. S.O.1456 (E). dated. 24.08.2007 has appointed the following members to Dargah Committee, Dargah Khwaja Sahab, Ajmer for a period of five years.

i.	Janab Nawab Mohammed Abdul Ali Sahab	Chennai.
ii.	Janab Haji Hafiz Wakil Ahmed Sahab	Sultanpur.
iii.	Janab Mohammed Ilyas Qadri Sahab	Ajmer.
iv.	Professor (Dr.) Ibraheem Sahab	Delhi.
v.	Janab Sohail Ahmad Khan	Patna.
vi.	Janab A.H.Khan Chowdhury	Delhi.
vii.	Janab Mohammed Suhel Mohiyuddin Tirmizi Sahab	Ahmedabad.
viii.	Janab Badruddin Gulammohiyuddin Shaikh Sahab	Ahmedabad.
ix.	Janab Ghole Ismail Muallim Sahab	Raigad.

A Brief on Services Being Rendered by Dargah Committee

1. Daily presentation of flowers, sandal and candles on the Holy Shrine.
2. Management of Annual Urs of Hazrat Khwaja Usmani (R.A.) in Shawwal.
3. Management of Muharram Sharif inside Dargah Sharif and opening of Chilla of Hazrat Baba Farid (R.A.).
4. Fateha of Khulfa-e-Rashedeen and Buzurgan-e-Deen.
5. Running of Darul Uloom Moinia Usmaniya Dargah Sharif for providing Deeni Taleem.
6. Running of Khwaja Model School, (an English Medium School) duly recognized by the Government for imparting education along with basic knowledge of Theology and Moral education.
7. Management of Gharib Nawaz Computer Center.
8. Daily Langar for poor with special Sehri / Iftar arrangement during holy month of Ramzan.
9. Stipend to widows and needy persons.

10. Maintenance of Unani Dispensary and Unani Shafa Khana supplying medicines free of cost.
11. Scholarships to needy and meritorious students undergoing Medical, Engineering and other technical courses.
12. Maintenance of Idgah and Financial assistance to various mosques.
13. Burial of unclaimed dead bodies.
14. Arrangements of pure and safe drinking water in Dargah .
15. Good water arrangements for wazoo.
16. Providing Shamiyanas at the time of Urs and periodical Religious congregations.
17. Payment of Huqooq (Honorarium) to hereditary staff.
18. Programme on National Integration.

1. Projects /Activities Undertaken during 2007 -- 2008.

The mandate of the Dargah Committee is basically “ *Service to the Pilgrims* ” through “*Need Based Development*” of infrastructure and also propagation of the preachings of the Sufi Saint Hazrat Khwaja Moinuddin Chishty (R.A.)

For accomplishing the above tasks, continued efforts are necessary at all spheres. Accordingly, the Dargah Committee has undertaken the following projects / activities during February 2007 to January 2008.

- Security
- Management of Urs and Congregations.
- Protection / Development of Endowment and Properties.
- Amenities to Zaireen (Pilgrims).
- Administration.
- Staff Welfare.
- Finance.
- Education.
- Planning

2. Management of Urs and Congregations:-

The 795th Annual Urs was held in July 2007 in which around 6 lacs pilgrims visited the Shrine. The Urs was incident free with full infrastructure of amenities to the pilgrims. These arrangements were appreciated at National and International level. Various dignitaries including H.E. Governor of Rajasthan and Haryana also visited the Shrine to pay homage and put on record appreciations for Urs arrangements.

The Dargah Committee has also made all the arrangements for the Mini Urs of Muharram being celebrated in January 2008 and again the security and amenities to pilgrims are on the top of its agenda.

3. Protection / Development of Endowment and Properties:-

Apart from periodical development / maintenance, the Dargah Endowment and Properties are required to be protected on regular basis for the usage by the pilgrims.

Development is also necessary for the augmentation of income wherever such properties are let out. Legal matters are another aspect, which has to be taken care of. The Dargah Committee has met all out efforts in this line which are enumerated as follows:

- i. Undertook internally the valuation of properties of Shrine.
- ii. Conducted detailed survey inside the Dargah Premises to know the real status of 'Un-authorized Occupants'. The survey being very sensitive & risky in nature was conducted in midnights and onwards.
- iii. Preparation of Dargah Map for the first time.
- iv. During last 11 months succeeded in getting the possession of 20 properties which were under the possession of trespassers.
- v. After Legal battle, undertook land levelling of Eidgah and took possession of 27000 Sq./ft of land. The land is proposed to be developed for the pilgrims / general public.
- vi. Removed unauthorized possessions from the endowment namely Qutub Sahab Ka Chilla and took possession of around 7500 Sq./ft of land at prime location of Ajmer City.
- vii. Visited Madhya Pradesh and a few places at Rajasthan to expedite the matter of unauthorized possession of agriculture land worth around Rs. 1.5 Crores. The matters are at various stages of legal process.
- viii. The scarcity of the water is one of the basic problems of Ajmer. For Dargah the source of water is one spring (called Jhalra). In February 2007, the water level in the spring was 3.5 feet. To solve the water problem, a project was undertaken for restoration of the historical and hydro geological status of the Jhalra. As a result the water level is now 24-5 feet i.e. net increase of 21 Feet.
- ix. Construction / renovation of Sehan Chirag, a historical monument within the Dargah Premises.
- x. During the Annual Urs (July 2007), there was a problem with the two marble gates in Ahata-E-Noor, the front area of the Shrine. These gates are popularly known as Bab-E-Qadriya & Bab-E-Owasiya. Since these gates were security problem for the Zaireen, the services of Architect and skilled workers from Mumbai were obtained and the gates were strengthened with the Mughal Art touch.
- xi. The Sandla / Plaster of Sandal Khana Mosque (A Historical Mosque adjacent to Shrine) was giving a bad look which has now been replaced with the marble.
- xii. Similarly the Central part of western side of the Akbari Mosques (A Historical Mosque adjacent to Shrine) was giving a bad look due to loss of plaster. This has now been replaced with the marble.

4. Amenities to the Zaireen :

Round the clock Supply of pure drinking water to the pilgrims through nineteen feet water level storage in Jhalra and a latest water filter plant. New water supply pipe line from P.H.E.D. also supplements the water requirements.

- i. Round the clock supply of water for the wazoo etc. in Dargah Premises.

- ii. Hot water supply during the winter and cold water in summer.
- iii. Periodical renovation of Gharib Nawaz Guest House with latest installation of 1500 Ltrs. capacity boiler for hot water supply.
- iv. Uninterrupted electric supply with foolproof Generator arrangements in case of electricity failure.
- v. Installation of Shamiyanas to protect zaireen from seasonal hazards. The project for permanent arrangements of Shamiyans is in pipe line.
- vi. With the help of Government of India, Ministry of Tourism, Art & Culture and active involvement of Government of Rajasthan through Ajmer Administration the works of Vishram Sthali are under rapid progress. The infrastructure is meant to provide facilities /amenities to the zaireen of Dargah Khwaja Sahab. Various State Governments have also evinced interest in developing their State Pavilion Blocks for the pilgrims. Under the projects the stay arrangements for around 60,000 pilgrims and parking facility for 5000 buses / vehicles are envisaged. The construction of Administrative Block by C.P.W.D., is almost over. The matter for approach road from N.H.8 to Vishram Sthali is pending for want of funds.
- vii. Efforts to strengthen further the Unani and Homeopathic Dispensaries. Discussions are on with other NGO's who are interested to extend the medical facilities to the zaireen.
- viii. In view of sanitation problem around the Dargah Premises a proposal for reconstruction of Sulabh Complex near Tripoliya Gate has been sent to the Municipal Council, Ajmer for approval.
- ix. A piece of land near the Jhalra has been identified for construction of sanitation block, however the land is required to be developed before commencement of the project.
- x. The Space at Eidgah has been doubled for the Zaireen / general public.

5. Administration :

- i. Created a congenial atmosphere between the Committee on the one part and Sajjadanashin, Khadim and the Zaireen on the other.
- ii. Created website for putting Committee's "**Public Face**" for transparency and also to attract more donors.
- iii. Chalked out a scheme for optimal utilization of manpower by shifting the staff members who have been working on one section over the years.
- iv. Introduced the Annual Confidential Report system.
- v. Standardization of Formats for Widow Pension Scheme & Stipend to needy students etc. These financial helps are extended by the Dargah Committee.
- vi. Rationlisation of leave and other personnel records.
- vii. Computerization of accounts of the Committee.
- viii. The Guest House operation would be Computerized soon.

B. Finances

Depicted below is the Financial Status of The Dargah committee in term of an abridged Income & Expenditure account.

C

**Dargah Committee, Dargah Khawaja Sahabm Ajmer.
Abstract**

Previous Year		Current Year
651598	Opening Balance: As on 01.04.2008	472396
27804344	Estimated Income for the year 2008-2009	33781700
28455942	Total	34254096
	Estimated Expenditure for the Year 2008-2009	
23674257	Revenue Expenses	29407000
1009289	Capital Expenses	1500000
24683546		30907000
472396	Closing Balance: As on 31.03.2009	3347096
8900000	FDR's as on 01-04-2007.	
12200000	FDR's as on 31.03.2008	

F. Dargah Committee Meetings

The Dargah Committee has had 5 sittings during the year in connection with the affairs of Dargah Sharif.

G. Visit of V.V.I.P's/ V.I.P.

The visit of following dignitaries amongst others deserves to be recorded.

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Janab A.R. Kidwai Sahab, | H.E. Governor of Rajasthan & Haryana. |
| 2. Mrs. Vasundhra Raje Ji, | Chief Minister of Rajasthan. |
| 3. Janab Lal Jan Basha, | Chairman Joint Parliamentary Committee.. |
| 4. Janab Sujit Dutta Sahab, | Joint Secretary to Government of India. |
| 5. Janab S.M.Akhater Sahab, | Deputy Secretary to Government of India. |
| 6. Shri Laloo Prasad Yadav, | Hon'ble Rail Minister, Govt. of India. |
| 7. Shri Chandra Babu Naidoo, | Former C.M. of Andhra Pradesh. |
| 8. Dr. Shakil Ahmed Sahab, | Minister of State for IT and
Telecommunication, Govt. of India. |

9. Janab K.Rehman Khan Sahab, Dy. Speaker, Rajya Sabha.

H. Audit of accounts.

Audit of Accounts of Dargah Khawaja Sahab for the year 2006-07 have been carried out by Principal Accountant General's team, Jaipur from 5th February 2008 to 19th February 2008. A few suggestions, advices of normal nature as given by the audit would be complied with for further improvements.

I. Vote of Thanks

The President and Vice President in particular and all the Committee Members in general have rendered valuable guidance for smooth and successful administration of Dargah Sharif. There was spontaneous cooperation from the Dargah Committee which has resulted in smooth conduct of day to day functioning and special events like Urs and other conventional rituals.

I would be failing in my duties if I do not mention that there was very good support from the Ministry of Minority Affairs, Government of India and the District Administration Ajmer, Department of Police, Municipal Corporation, Electricity Board and other Public Utility service providers.

I conclude this report with a note that the year to come would also be eventful for which a vision document is under preparation.

AHMED RAZA
Nazim & Chief Executive Officer

**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India
on the Accounts of Dargah Khwaja Saheb, Aimer for the year ended 31
March 2008.**

We have audited the attached Balance Sheet of Dargah Khwaja Saheb (DKS), Ajmer as at 31 March 2008 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Accounts for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act 1971 read with Section 19(1) of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955. The audit has been entrusted for the period of five years with effect from 2003-04. These financial statements include the accounts of all units of the DKS. These financial statements are the responsibility of the DKS's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc, Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:-
- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Controller General of Accounts of India.
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the DargahKhwaja Saheb, Ajmer as required under section 20 (2) (d) of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955 in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv. We further report that:

Comments on Accounts

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities Rs. 6.05 Crore

Secured Loans and Borrowings Rs. 0.19 Crore .

Interest Accrued - on loans / Borrowings

Interest on II, III, IV Loan (received from Central Waqf Council , New Delhi) was paid upto 16-12-2007, 17-03-2008 & 14-02-2008 respectively but provisions of interest due upto 31-3-2008 was not made. As a result liability of Rs. 0.18 lakh was understated and expenditure was also understated to this extent.

A.2 Assets Rs. 6.05 Crore.

- (i) One time vehicle tax of Rs.0.20 lakh was paid but it was not capitalized. As a result fixed assets were understated and expenditure was overstated to this extent.

Similar comment of Rs. 0.51 lakh was taken in the report of 2006-07 but effect was not carried out in the accounts.

- (ii) This is understated by Rs. 0.51 lakh as the construction work was carried out for Rs.3.51 Lakhs but in books it was taken only Rs.3.00 lakhs. The amount of security deposit and 10% withheld money deducted from the bill was not shown as liability. As a result liabilities of Rs. 0.51 lakh was also understated.
- (iii) This is overstated by Rs.5.09 lakh as the construction of Khwaja Model School not yet completed. As such "work in progress" was understated to the same extent.
- (iv) This is understated by Rs. 1.68 lakhs as the new nine toilets were constructed but not capitalized. As a result, the expenditure of Rs. 1.68 lakh was overstated.

This comment was pointed out in the year 2006-07 but no action was taken.

A.3 Current Assetts – Loans & Advances etc. Rs. 1.62 Crore.

- (i) This is understated by Rs.0.30 lakhs being the expenditure incurred on computer consumables like floppies, toners etc., which was reimbursable from National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL) Department of Secondary and Higher Secondary Education, Govt. of India, New Delhi but was charged as computer center expenses in the income & Expenditure account in place of showing the amount as receivable from NCPUL. This also resulted in overstatement of expenditure to the same extent.

Similar comments of claims receivable of Rs.0.22 lakhs was also taken in the year 2006-07, but effect was not given in the Balance Sheet for the year 2007-08.

- (ii) This is understated by Rs. 2.79 lakhs as security for electrical connection deposited to AVVN Ltd., Ajmer in earlier year's but it was not shown in the "Current Assets, Loans & Advances" . As a result capital fund was also understated to the same extent.
- (iii) This is understated by Rs. 0.045 lakh as the advances paid to secondary school examinations for affiliation for the period 01.04.2008 to 31.3.2011 was not shown in the Loans & Advances. As a result loans advances were understated and expenditure was overstated to this extent.

B. Income & Expenditure Account:-

B.1 Expenditure Rs. 2.49 Crore.

- (i) Expenditure of Rs. 1.03 lakh was overstated as the moveable assets like Dari- Gadella , Quilts etc. were booked in the Income and Expenditure A/cs. As a result assets were also understated to this extent.
- (ii) This is overstated by Rs. 0.33 lakh as the employee's contribution for Employees State Insurance paid by Dargah Committee was not recovered from concerned employee's . As a result current assets were also understated to the same extent.
- (iii) This is overstated by Rs.5.97 lakhs as the equipment / electronics items were purchased for security measures but not capitalized. As a result fixed assets were also understated to the same extent.
- (iv) This is overstated by Rs.2.37 lakhs as the expenditure incurred on development of land, leveling and cleaning of site at Chilla Qutub Sahab was not capitalized. As a result assets were understated to the same extent.

- (v) This is overstated by Rs. 1.74 lakh as the expenditure incurred on installation of new gate, leveling of the site at Idgah Subji Mandi were not capitalized. As a result fixed assets were also understated to the same extent.

B.2 Income Rs. 2.57 Crore.

This is understated by Rs.2.26 lakhs being room rent not received from members / zaireen during the year 2006-07 was not accounted for. This also resulted in understatement of current assets 'Loans & Advances' to this same extent. This was pointed out in the year 2006-07 but no action was taken.

C General :-

1. The accounts of the Dargah were being audited by a Chartered Accountant firm in contravention of the standard terms and conditions (conditions) prescribed for taking up audit under section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Power and Conditions of service) Act 1971.
Similar comment was also made in the Audit Report of 2006-07.
- 2(i) Depreciation has not been charged on immovable assets i.e buildings.
Similar comment was also made in the Audit Report of 2006-07.
- 2(ii). Depreciation on moveable assets purchased during the year were not charged on prorata basis.
3. Rental Income and lease Money Rs. 0.21 lakhs have been written off during the year without the approval of the Dargah Committee.
Similar comment of Rs. 2.46 lakhs was also taken in the report of 2006-07 but approval of Dargah Committee for write - off not obtained so far.

- 4(i) Donation of Rs. 1.00 lakhs was received for sandal fund but the same have been shown under schedule "Corpus capital Fund" in place of earmarked / endowment funds, as the fund was received for specific purpose.
- (ii) Donation of Rs.8.50 lakhs for construction of Guest House building in 'G Block' and construction of school was received during the year 2006-07 but the same have been shown under schedule "Corpus Capital Fund" in place of Earmarked / Endowment Fund, as the funds was received for specific earmarked purpose. Comment was pointed out in Audit Report for the year 2006-07 but no remedial action was taken.
- (iii) An Investment of Rs.1.22 crore was made with the schedule and non-schedule Bank. This has been included in schedule-11 in Bank Balance in place of schedule-10, Investment -- others.

This comment was pointed out in Audit Report for the year 2006-07 but no remedial action was taken.

5. The significant accounting policy appended with the accounts as schedule-24 indicates that:-

- (i) Liability towards gratuity payable on death / retirement of employees needs to be accrued on actuarial basis.
- (ii) Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefits at the end of each year.

On scrutiny of records, It was noticed that no such provision have been made and shown in the accounts under schedule -7. Current liabilities and provisions.

6. There was no stock entry of 10 numbers of Silver bowls worth Rs.0.17 lakh received as donation for Dargah Sharif. The possession of the same was also not found with the management.

This comment was pointed out in the Audit Report for the year 2006-07 but no action was taken.

7. Government of Rajasthan has allotted the 0.56 hectare land in Junia village, Distt Ajmer but in schedule A.1 , it has been shown as 0.46 hectare.

Effect of Audit comments on Accounts:

The net impact of the comments given in preceding paras is that as on 31st March 2008, assets were understated by Rs. 19.96 lakh, liabilities understated by Rs. 3.48 lakh and excess of Income over expenditure under stated by Rs.16.48 lakh.

D Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, We report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account / Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters, stated above and other matters mentioned in Annexure- I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer as at 31 March 2008, and
- b. In so far as it relates to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.
- vii. Draft Audit Report was issued on 6.4.2009 followed by reminder dated 8-6-2009 but the reply has not been received so far, therefore the comments mentioned therein are treated as verified.

For and on behalf of the C&AG of India

Place : Jaipur

Date : 15-08-2009

Principal Accountant General (Civil Audit)
Rajasthan, Jaipur

Annexure-I to Audit Report**1. Adequacy of Internal Audit System**

Internal audit system prevailed in the Dargah is not adequate. The said Internal auditor (Chartered Accountant) checks and prepares final accounts only.

2. Adequacy of Internal Control System.

Internal Control System prevailed in the Dargah was evaluated during audit and the following position emerged:-

3. (I) General

- (i). There is no Plan of rotation of duties of employees with cash, stock and other valuables items.
- (ii) There is no system of preparing and awarding the licenses to Khadims as to regulate their functions in Dargah.
- (iii) There is no control over money dropped by Zaireen into cauldrons.
- (iv) Advisory committee as mentioned in the sections 10 of the Dargah Khwaja Saheb, Act has not been constituted till now.

(II) Cash & Bank.

- (i) There are number of types of receipts book. Computers Center receipts books and Khwaja Model School receipt books were got printed by themselves respectively. In order to monitor all the receipts, one type of receipts book should be printed.

(ii) Unused receipts books are in the possession of cashier in place of store keeper.

(iii) Unused receipts books were not checked physically.

(III) Purchase and Sales

(i) Purchases are not centralized.

(ii) Material/ Supply is received by different departments in place of Central Store.

(iii) Purchase order register having details of each purchase from beginning to end, is not maintained.

(IV) Fixed Assets.

(i) Updation of the property register was not done. Moveable assets were not included in the register. Figures of register are not reconciled with accounts.

(ii) There is no system to certify that all property are in their possession and their is no encroachment.

(iii) There is no written procedure for physical verification .

(iv) Bulldings are not insured with respect to fire, riot and civil commotion etc.

(V) Stock.

There is no norms for stock level of raw material viz, Sugar, Rice, Wheat, Sandal etc, to hold at minimum and maximum stock level.

S. K. BHARGAVA
Sr. Audit Officer/IC-III

Annual Administrative Report
Of
Dargah Committee Dargah Khwaja Sahab(R.A.), Ajmer
For The Year 2008-2009

It is my privilege and also a matter of immense pleasure to make a presentation on the Administrative aspects of Dargah Committee, Dargah Khwaja Sahab of Ajmer for the year 2008-2009. As usual the Dargah Management has worked in full swing during the current year. An account of the such activities is given in foregoing paras.

I. The Management:

The following Members of the Dargah Committee appointed by the Government of India, vide Gazette Notification No. S.O.1456 (E). dated. 24.08.2007 have continued their dedicated services during the reporting period for the noble cause of the Committee.

i.	Janab Nawab Mohammed Abdul Ali Sahab	Chennai.
ii.	Janab Haji Hafiz Wakil Ahmed Sahab	Sultanpur.
iii.	Janab Mohammed Ilyas Qadri Sahab	Ajmer.
iv.	Professor (Dr.) Ibraheem Sahab	Delhi.
v.	Janab Sohail Ahmad Khan	Patna.
vi.	Janab A.H.Khan Chowdhury	Delhi.
vii.	Janab Mohammed Suhel Mohiyuddin Tirmizi Sahab	Ahmedabad.
viii.	Janab Badruddin Gulammohiyuddin Shaikh Sahab	Ahmedabad.
ix.	Janab Ghole Ismail Muallim Sahab	Raigad.

II. A Brief on Services Being Rendered by Dargah Committee


1. Daily presentation of flowers, sandal and candles on the Holy Shrine.
2. Management of Annual Urs of Hazrat Khwaja Usmani (R.A.) in Shawwal.
3. Management of Muharram Sharif inside Dargah Sharif and opening of Chilla of Hazrat Baba Farid (R.A.).
4. Fateha of Khulfa-e-Rashedeen and Buzurgan-e-Deen.
5. Daily Langar for poor with special Sehri / Iftar arrangement during holy month of Ramzan.
6. Running of Darul Uloom Moinia Usmaniya Dargah Sharif for providing Deeni Taleem.
7. Running of Khwaja Model Secondary School, (an English Medium School) duly recognized by the Government for imparting education along with basic knowledge of Theology and Moral education.
8. Management of Gharib Nawaz Computer Center.
9. Stipend to widows and needy persons.

10. Maintenance of three separate dispensaries viz. Unani, Homeopathic and Allopathic Dispensaries where apart from the consultations the medicines were provided free of cost.
11. Scholarships to needy and meritorious students undergoing Medical, Engineering and other technical courses.
12. Maintenance of Idgah and Financial assistance to various mosques.
13. Burial of unclaimed dead bodies.
14. Arrangements of pure and tripled filtered safe drinking water in Dargah.
15. Good water arrangements for wazoo. Hot water is supplied three times during the winter season.
16. Providing Shamiyanas in Dargah Premises to protect the zaireen from seasonal hazards. Similarly shelters are also provided at the time of Urs and periodical Religious congregations.
17. Payment of Huqooq (Honorarium) to hereditary staff.
18. Programme on National Integration.
19. Programme for Legal Literacy among the weaker section of the society.
20. Provision of infrastructure and supervision for the examinations conducted by the Rajasthan Public Service Commission and Revenue Department.
21. Provision of Security Infrastructure including X-ray Machine and Cameras.

III. Projects /Activities Undertaken during 2008-2009.

The mandate of the Dargah Committee is basically “ *Service to the Pilgrims* ” through “ *Need Based Development* ” of infrastructure and also propagation of the preaching's of the Sufi Saint Hazrat Khwaja Moinuddin Chishty (R.A.)

For accomplishing the above tasks, continued efforts are necessary at all spheres. Accordingly, the Dargah Committee has undertaken the following projects / activities during the year 2008-09.

1. Computerization of records of Properties, Accounts, Nazurat and Guest House.
 2. Search for the Properties of Dargah Committee lying in various parts of the country, it's identification, liason with Revenue Authorities, legal action and vigorous follow up thereof. Properties worth lakhs of rupees have been taken into possession by the Committee.
 3. Legal Action and campaign against the unauthorized occupants. The possessions of properties worth crores of rupees have already been taken.
 4. Conducted survey and prepared maps, drawings and cost estimates for development of five big properties in Ajmer which are meant for providing amenities to pilgrims.
- 

5. Renovation of reservoir '*Jhalra*' has been considered as a national project by the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, Government of India.
6. Legal Action against 100 tenants / persons is on to safeguard the interest of Dargah Committee.
7. Renovation of Nazur Office of Dargah Committee.
8. Renovation of a Part of Sandal Khana Masjid.
9. Periodical renovation of Gharib Nawaz Guest House.
10. Un-interrupted Electric Supply with foolproof arrangements of generators in Dargah Premises and Guest House.
11. The boundary wall of Vishram Sthali, spread over 230 Bighas has been completed. Similarly, the works relating to water tank have also been commenced. Tenders for the 1st block, consisting of 28 Dormitories have been finalized. Also the tenders for electric and water supply are under process. The house is aware that this project is financed by Govt. of India / Govt. of Rajasthan and execution is carried by CPWD. The works are coordinated by the Dargah Committee.
12. On our request a team of experts under the leadership of Dr. Hamida Abdi, Advisor, Ministry of Technology & Science visited our office in connection with the project "Flowers of Mazar Sharif". The house is aware that the flowers are presently dumped into a well on which the Committee is spending Rs. 1.5 Lakh per annum. With an object to utilize these flowers with all *Taqaddus* and economy the team has conducted the survey and confirmed the technical feasibility of the project. The salient features of the same are as follows:
 - Arq-E-Gulab shall be extracted from the flowers which are now dumped into well.
 - Similarly there could also be Agarbatti Production from the material available after extraction of Arq-E-Gulab.
 - The material left after the above two process can be converted into manure.
 - Around 30 to 40 people shall get the employment opportunity.
 - There will be substantial income to the Dargah Committee from the marketing of the above products.

IV. Management of Urs and Congregations:-

The 796th Annual Urs was held in July 2008 in which around 5 lacs pilgrims visited the Shrine. The Urs was incident free with full infrastructure of amenities provided to the pilgrims. These arrangements were appreciated at National level. Various dignitaries also visited the Shrine to pay homage to the Great Sufi saint.

The Dargah Committee has also made all the arrangements for the Mini Urs. The Committee records it's sincere thanks to the Distt. Administration, Police, Intelligence Agencies and the Local Bodies for their spontaneous cooperation.

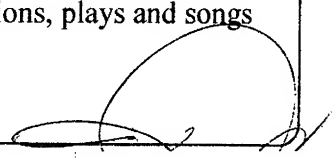
V. Administration :

- I. Maintenance of congenial atmosphere between the various stake holders / Operating Agencies viz: Sajjadanashin, Khadim and Zaireen is really a challenge in view of various issues inherited by the Dargah Committee. However during the reporting period efforts were made to keep live contact with all to defuse the tension cropping up due to one or other reasons. Your Committee has maintained respectable relationship with all. The only *Mantra* for this is to execute committee's programme exclusively as per various provisions laid down in Act and Bye Laws.
- II. Introduction and periodical up-dation of Website has worked as a public face of the Committee which has also helped in maintaining the transparency. Publication of Committee's booklet has really played crucial role in bringing among the Public the real status of Dargah Committee. This has also resulted in increase the income from the donation.
- III. Computerization, standardization of formats and rationalization in maintenance of records has increased the reputation of the Committee.
- IV. Harmonious relationship with the Distt. Administration, Police Department and State Government has brought the Committee on the map of the State. The Distt. Administration and Police also cooperated a lot in execution of various verdicts from Hon'ble Courts.

VI. FUNCTIONING OF KHWAJA MODEL SECONDARY SCHOOL, AJMER.

Consequent upon the affiliation by CBSE for the secondary status the Committee, acted swiftly with double zeal and as a result the enrollment gone up from 316 to 425 a quantum jump in a year. On academic side, the standard has been considerably improved by virtue of extra classes, Keeping vigilant eye on the performance of students individually and special classes for average and boundary line students were the other efforts of the Committee to bring further improvements . With an object to bring the students out of shell, spoken English classes were the value addition. For ethical values the theology is also taught. Where the Urdu language is adding the flavor,. the Sanskrit shall be implemented from April 2009. The joint efforts by teaching staff has brought colorful results with 90% of students have secured respectable position.

The other areas of concentration by the school administration are to develop rich social and moral abilities through cultural and co-curricular activities. For this purpose marshalling of the students has been done according to classes and age groups. Debate, healthy competitions, speeches, group discussions, plays and songs are the tools to sheen the talents of the students.



The school has entered very rapidly into the main stream and accordingly the Govt. of Rajasthan has earmarked our School for RAS exam and exams for the Revenue Department Employees.

For acquiring and sharpening the knowledge of students, Educational Trips have been undertaken and similarly for pre- primary and primary students picnic parties have been arranged.

Games and sports are equally close to our heart and therefore the Annual Athletic meet consisting of all types of games - events have been arranged in December 2008.

Imparting education to the children of weaker section and downtrodden strata of the society is on the top of the Agenda and the Committee has been implementing it in toto.

As far as the infrastructure is concerned the Committee has already expanded the school building whereas the construction of first floor consisting of 12 halls has already been approved. The Dargah apartments (Civil Lines) has been earmarked as school hostel. Provision of science lab, Computer lab, modern canteen have also been made in the plan.

VII. Functioning of Darul Uloom Moinia Usmaniya:-

The Committee has been successfully managing *Darul Uloom Moinia Usmaniya*, a school of theology which is also imparting the preaching's of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz. The Darul Uloom has highly qualified five number of Aalim, Fazil, Kamil, Hafiz, Qari and Librarian. There are seventy seven number of students in the classes viz: Edadiya, Oola, Saniya, Rabiya, Tehtaniya and Hifz. The Committee has also made lodging and Boarding arrangements for 65 number of students. Efforts are also on to construct a suitable building for Darul Uloom with all facilities to the students including recreation facility.

VIII. Finances

Depicted below is the Financial Status of The Dargah committee in term of an abridged Receipt and Payments A/C.

Dargah Committee, Dargah Khawaja Sahab, Ajmer.**BUDGET PROPOSALS**

Major Heads	Income Rs. (In lakhs)		
	2008-2009		2009-10
	Actuals	Budgeted	Budgeted
Jagirs	2.75	3.06	2.78
Rent From Properties	41.69	41.35	40.25
Donations & Nazur	154.89	147.80	164.35
Guest House	107.61	102.00	122.00
Donations for Developmental Works	00.00	11.00	00.00
Education	16.63	16.00	22.50
Miscellaneous	20.68	16.60	23.30
Total	344.25	337.81	375.18

Dargah Committee, Dargah Khawaja Sahab Ajmer.**BUDGET PROPOSALS****EXPENDITURE**

Major Heads (A) Revenue Expenses	Expenditure Rs. In lakhs		
	2008-2009		2009-2010
	Actuals	Budgeted	Budgeted
Salaries & Allowances	103.29	104.02	136.48
Office Expenses	19.15	21.80	22.00
Dargah sharif Expenses	*96.79	70.45	78.35
Mazar sharif Expenses	8.24	7.76	9.79
Medical facilities	1.48	2.20	1.95
Darululoom Expenses	3.87	4.00	4.15
Khwaja Model School Expenses	11.28	28.95	12.10
Computer Centre Expenses	3.81	2.90	5.40
Educational Aid	2.77	3.00	3.50
Welfare & Charities	11.24	17.44	18.40
Guest House Expenses	25.76	25.85	27.00
Dargah Apartments Expenses	1.29	2.50	2.30
Repairs & Renewals	1.63	1.00	2.00
Miscellaneous	2.55	2.20	2.20
School Building Construction	15.57	15.00	40.00
Total	308.72	309.07	365.62

*Includes the expenditure incurred on Security Infrastructure.

Major Heads	Expenditure Rs. In lakhs		
	2008-2009		2009-2010
	Actuals	Budgeted	Budgeted
1. Developmental Works (Capital Expenses)			
2. Wall to Protect School Building from Nala	*1.83		--
3. Construction of toilets	1.09		5.0
4. Development of Various Properties at Ajmer	0.80		
5. Construction of Nazur Office	2.12		
6. Donations received in Kinds & Consumed	16.04		
6. School Bus	10.52		
Sub Total	32.40		
Total (B)	32.40	00.00	5.00
Total (A)	308.72	309.07	365.62
	341.12	309.07	370.62

* This works has resulted into reclamation of property worth Rs.50 lakhs.

IX. Dargah Committee Meetings

The Dargah Committee has had 5 sittings during the year in connection with the affairs of Dargah Sharif.

X. Visit of V.V.I.P's/ V.I.P.

The visit of following dignitaries amongst others deserves to be recorded.

1. Janab S.K.Singh Sahab,
2. Shri. Ashok Gehlot Ji,
3. Janab Lal Jan Basha,
4. Janab Sujit Dutta Sahab,
5. Janab S.M.Akhater Sahab,
6. Shri Laloo Prasad Yadav,
7. Smt. Salma Ansari Saheba,
8. Kumari Selja,
9. Smt.Panabaaka Lakshmi

H.E. Governor of Rajasthan.
Hon'ble Chief Minister of Rajasthan.
Chairman Joint Parliamentary Committee..
Joint Secretary to Government of India.
Deputy Secretary to Government of India.
Hon'ble Rail Minister, Govt. of India.
Wife of Vice President of India..
Hon'ble Minister of State for Housing & Urban Poverty Alleviation, Govt. of India.
Hon'ble Union Minister of State Health & Family Welfare..

XI. Audit of accounts.

Audit of Accounts of Dargah Committee for the year 2007-08 has been carried out by Principal Accountant General's team, Jaipur from 27th January 2009 to 11th February 2009. A few suggestions, advices of normal nature given by the audit would be complied with for further improvements.

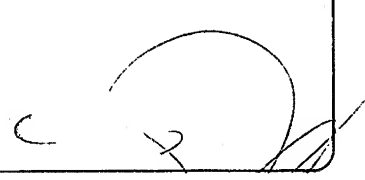
XII. Vote of Thanks

The President and Vice President in particular and all the Committee Members in general have rendered valuable guidance for smooth and successful administration of Dargah Sharif. There was spontaneous cooperation from the Dargah Committee which has resulted in smooth conduct of day to day functioning and special events like Urs and other conventional rituals.

I would be failing in my duties if I do not record the good support received from the Ministry of Minority Affairs, Government of India. The District Administration Ajmer, Department of Police, Municipal Corporation, Electricity Board and other Public Utility service providers also extended excellent support.

I conclude this report with a note that the year to come would also be eventful.

AHMED RAZA
Nazim & Chief Executive Officer



**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India
on the Accounts of Dargah Khwaja Saheb, Aimer for the year ended 31
March 2009.**

We have audited the attached Balance Sheet of Dargah Khwaja Saheb (DKS), Ajmer as at 31 March 2009 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Accounts for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act 1971 read with Section 19(1) of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955. The audit has been entrusted for the period of five years with effect from 2003-04. These financial statements include the accounts of all units of the DKS. These financial statements are the responsibility of the DKS's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc, Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:-
 - i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Controller General of Accounts of India.
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the DargahKhwaja Saheb, Ajmer as required under section 20 (2) (d) of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955 in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv. We further report that:

Comments on Accounts

A. BALANCE SHEET:-

A.1 Liabilities Rs.6.96 Crore.

Provision for Rs. 1.07 lakh (Rs. 1.00 lakh as ex-gracia payment to the families of a deceased/injury person during a mishap held on 11.10.2007 and payment of outstanding bill of diesel & petrol of Rs. 6926 in the year 2003) was made. Since the where about of deceased families could not be traced out, therefore, Dargah Committee decided not to pay the ex-gracia payment and also diesel & petrol bills, but no action to adjust the provision was taken. This has resulted in over statement of current liabilities and understatement of income amounting to Rs. 1.07 lakh.

Dargah accepted the facts and stated that necessary reversal entry shall be passed to rectify this error.

A.2 Assets Rs. 6.96 Crore**A.2.1 Fixed Assets Rs. 4.53 crore**

- (i) This was over-stated by Rs. 16.34 lakh as the construction of Khawaja Model School has not yet been completed. As such work in progress was understated to the same extent.

Dargah accepted the facts and stated that necessary adjustment shall be carried out during the current financial year.

- (ii) This was understated by Rs. 1.27 lakh as the software for various works procured was shown as an expenditure. This has also resulted in understatement of surplus to the same extent.

Dargah accepted the facts and stated that necessary adjustment shall be carried out during the current financial year.

B. Income & Expenditure Account.**B.1 Expenditure - Rs. 3.28 Crore.**

An amount of Rs. 6.67 Lakh was written-off at asset side and the effect of this was made in capital fund instead of Income & Expenditure account.

As a result capital fund was understated and the surplus was overstated to the same extent.

Dargah accepted the facts and stated that the assets which have become obsolete should be written off and such loss be shown in Income & Expenditure Account.

C. General

Earmarked/Endowment fund for Rs. 9.50 lakh (Donation received Rs. 8.50 lakh for construction of guest house building and a school and Rs. 1.00 lakh for sandal wood) created during the year 2007-08 has been included with capital fund during the year 2008-09. Since the donations were for specific purposes, therefore, this was to be shown under separate head Earmarked/Endowment fund.

Dargah stated that the capital fund of Rs. 9.50 lakh was created in compliance of audit comment and in subsequent year this fund was merged into the capital fund. The amount of this fund was invested in the FDRs.

This accounting treatment by Dargah is not correct. This fund should have been shown separately as Earmarked/Endowment fund and the FDRs as the earmarked/endowment fund investments.

Effect of Audit on Accounts:

The net impact of the comments given in preceding paras is that as on 31st March 2009, assets were under-stated by Rs. 1.27 lakh liabilities under-stated by Rs. 5.60 lakh and surplus was overstated by Rs. 4.33 lakh.

D Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, We report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account, Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters, stated above and other matters mentioned in Annexure- I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India,

- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer as at 31 March 2009, and
- b. In so far as it relates to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Place : Jaipur

For and on behalf of the C&AG of India

Date : 29.10.2010

Principal Accountant General (Civil Audit)
Rajasthan, Jaipur

Annexure-1 to Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System:

Internal audit system prevailing in the Dargah is not adequate. Chartered Accountant prepared final accounts only.

2. Adequacy of Internal Control System:

Internal Control System prevailing in the Dargah was evaluated during audit and the following position emerged:

General:

- (i) There is no plan of rotation of duties of employees with cash, stock and valuable items.
- (ii) There is no system of preparing and awarding the licenses to Khadims to regulate their functions in Dargah.
- (iii) There is no control over money dropped by Zaireen into cauldrons.
- (iv) Advisory Committee, as mentioned in the section 10 of the Dargah Khwaja Saheb, Act has not been constituted till now.

II - Cash and Bank

- (i) There are number of types of receipt books i.e. General receipt book, computer center receipt book and khwaja Model School receipt books. These are printed by themselves so there is no control over use of receipt book. In order to monitor all the receipts one type of receipt book should be printed.
- (ii) Unused receipt books are in the possession of the cashier in place of storekeeper.
- (iii) Unused receipt books were not physically checked.

III - Purchases and Sales:

- (i) Purchases were not centralized.
- (ii) Material supply was being received by different departments in place of Central Store.
- (iii) Item - wise purchase register having all the details, has not been maintained.

IV - Fixed Assets:

- (i) Updation of the property register was not done. Moveable assets were not included in this register. Figures of register are not reconciled with accounts.
- (ii) There is no system to certify that all the property are in their possession and there is no encroachment.
- (iii) There is no standard system to evaluate the value of Gold and Silver ornaments received by the Dargah Committee in Donation.
- (iv) There is no system for physical verification of assets.
- (v) Buildings are not insured with respect to fire, riot and civil commotion etc.

Naveen

Assistant Accountant General/IC-III